माघ कृष्ण - 7 | संवत 2080 | वर्ष - 19 | अंक - 188 | पृष्ठ - 8 | रु. 5/- | बेंगलूरु » शुक्रवार » 02-02-2024 | www.dakshinbharat.com | Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 कार हादसे के बाद पैर खोने का डर था : पंत

6 दशकों बाद देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

7 देव आनंद की फिल्मों की पुरानी यादगार चीजों की ऑनलाइन होगी नीलामी

फर्स्ट टेक

अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण, 56 मिनट में रखी अपनी बात

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया और 56 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त किया जो उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। फिरोजी रंग की कढ़ाई वाली कांथा सिल्क की साड़ी पहनकर संसद पहुंचीं सीतारमण के भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी घोषणाओं और टिप्पणियों पर बीच-बीच में मेजें थपथपाते देखे गए। जब उन्होंने कहा कि ''हमारी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी'' तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सबसे ज्यादा देर तक मेजें थपथपाईं।

जम्मू-कश्मीर राजमार्ग यातायात के लिए बंद, 200 से अधिक वाहन फंसे

बनिहाल/जम्मू/भाषा। रामबन जिले में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बृहस्पतिवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया जिससे 200 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। राजमार्ग पर भी कई स्थानों पर फिर से बर्फबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन जिले के शेरबीबी इलाके में हुआ जहां भारी बारिश भी हुई। यातायात पुलिस ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर शेरबीबी के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और यातायात बहाली का काम शुरू होने वाला है। राजमार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर 200 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं।

इमरान खान की पार्टी के मुख्यालय पर छापा

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सादे लिबास में पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने यहां इसके मुख्यालय पर कथित तौर पर छापा मारा तथा पार्टी के सदस्यों को परिसर में प्रवेश करने से रोका। पार्टी सूत्रों के हवाले से 'डॉन न्यूज' ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह छापेमारी खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद हुई

सूर्यास्त 02-02-2024 6:20 बजे	सूर्योदय 03-02-2024 6:45 बजे
BSE 71,645.30 (-106.81)	NSE 21,697.45 (-28.25)
सोना 6,515 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 74,174 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

ईडी राग

ईडी ने छेड़ा नेह-राग,
हो गई शुरू माथाफोड़ी।
सोरेन हो गए आज बैन,
कर रहे आज हाथाजोड़ी।
फंडिंग का भण्डाफोड़ हुआ,
तथ्यों से अब मोड़ा-मोड़ी।
सम्मन होने लग गए जारी,
मचने लग गई भागादौड़ी।।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 6.1 प्रतिशत बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। व्यय में वृद्धि और पूंजीगत व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन के कारण बजट का आकार बढ़ा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, संशोधित अनुमान के अनुसार उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। इसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति 30.03 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह पूर्व में जताए गए अनुमान से अधिक है। यह प्राप्ति अर्थव्यवस्था में वृद्धि की मजबूत गति और संगठित रूप को दर्शाती है।

राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत है। बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि अनुमान में कमी के बावजूद राजकोषीय घाटे में सुधार है। अगले वित्त वर्ष के लिए बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत आंकी गई है। यह पहले के 11 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले कम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाजार मूल्य पर जीडीपी 3,27,71,808 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

गरीब, महिलाओं, युवा और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की चार ''प्रमुख जातियों- गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों'' की आकांक्षाओं व जरूरतों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार विकास की सोच के साथ काम कर रही है जो सभी के लिए हो, सर्वव्यापी हो और सर्व-समावेशी हो। उन्होंने कहा, यह सभी स्तर पर सभी जातियों और लोगों के लिए है। हम 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें लोगों की क्षमता को उन्नत करने और उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है। सीतारमण ने कहा कि 'चार प्रमुख जातियों' पर ध्यान देने की जरूरत है, जो हैं गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। उन्होंने कहा कि इनकी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वित्त मंत्री ने आम चुनाव से पहले अपने बजट भाषण में कहा, देश तभी तरक्की करता है, जब ये तरक्की करते हैं। इन चारों को उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में सरकार का समर्थन चाहिए और मिलता है। उनके सशक्तीकरण और भलाई से देश आगे बढ़ेगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट से जुड़ी मुख्य बातें

- बुनियादी ढांचा के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा।
- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी।
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया।
- आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया।
- खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए किया गया।
- पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया।
- वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई।
- विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत की गई।
- वित्त वर्ष 2024-25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना।
- वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल तथा शुद्ध बाजार उधारी क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगल पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।
- छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी।

बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम आम बजट को 'ऐतिहासिक, समावेशी और नवोन्मेषी' करार दिया और कहा कि यह बजट 2047 के 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के जरिए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है जो विकसित भारत के चार स्तंभों क्रमश: युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा, आज का ये बजट समावेशी और नवोन्मेषी बजट है। इस बजट में निरंतरता का विश्वास है।

ज्ञानवापी : खोला गया व्यास जी का तहखाना, सफाई के बाद हुई पूजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाराणसी (उप्र)/भाषा। वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहख़ाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के चंद घंटे बाद बुधवार देर रात तहखाने को खोलकर उसकी साफ सफाई की गई और फिर वहां पूजा की गई।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूर्व की तरह अब पूजा पाठ नियमित किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज करते हुए इसे नियत प्रक्रिया से परे गतिविधि करार दिया है। पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास ने बृहस्पतिवार को 'पीटीआईभाषा' को बताया कि अयोध्या स्थित नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ की अगुआई में बुधवार देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा कराई। इस दौरान जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मण्डलायुक्त कौशल राज शर्मा और पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन तथा मंदिर के कई ट्रस्टी मौजूद थे।

पूजा की अनुमति के निर्णय को चुनौती दी

प्रयागराज/भाषा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाना में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति देने के वाराणसी की अदालत के निर्णय को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बृहस्पतिवार को रुख किया। इंतेजामिया कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के महानिबंधक के समक्ष आवेदन किया है। अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है।

अभियानगत तैयारियों को और मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है सेना : जनरल पांडे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे/भाषा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय सेना एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है और इसने अभियानगत तैयारियों को और मजबूत करने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की है।

जनरल पांडे ने महाराष्ट्र के पुणे में 'बॉम्बे सैपर्स वॉर मेमोरियल सैंटिनरी' के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सेना की रेजीमेंट और अन्य

यूनिट में अग्निवीरों का एकीकरण एक अहम मुद्दा है और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जनरल पांडे ने कहा कि बॉम्बे सैपर्स का इतिहास शौर्य, बलिदान और साहस से भरा है। इसने युद्ध के मैदान में, शांतिकाल में, खेल में और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के माध्यम से नाम कमाया है। उन्होंने कहा, ''राष्ट्र निर्माण कार्यों में बॉम्बे सैपर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि यह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करता रहेगा और भारतीय सेना का नाम ऊंचा रखेगा।

जनरल पांडे ने कहा, भारतीय सेना परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है और इसके लिए इसने पिछले वर्ष व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इस बदलाव का मकसद अभियानगत तैयारियों को और मजबूत करना साथ ही हमारी कार्य संबंधी और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। हमने बदलाव की राह में अच्छी प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि इस बदलाव के तहत भारतीय सेना का जोर 'कोर ऑफ इंजीनियर्स' में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का समावेश करना है।

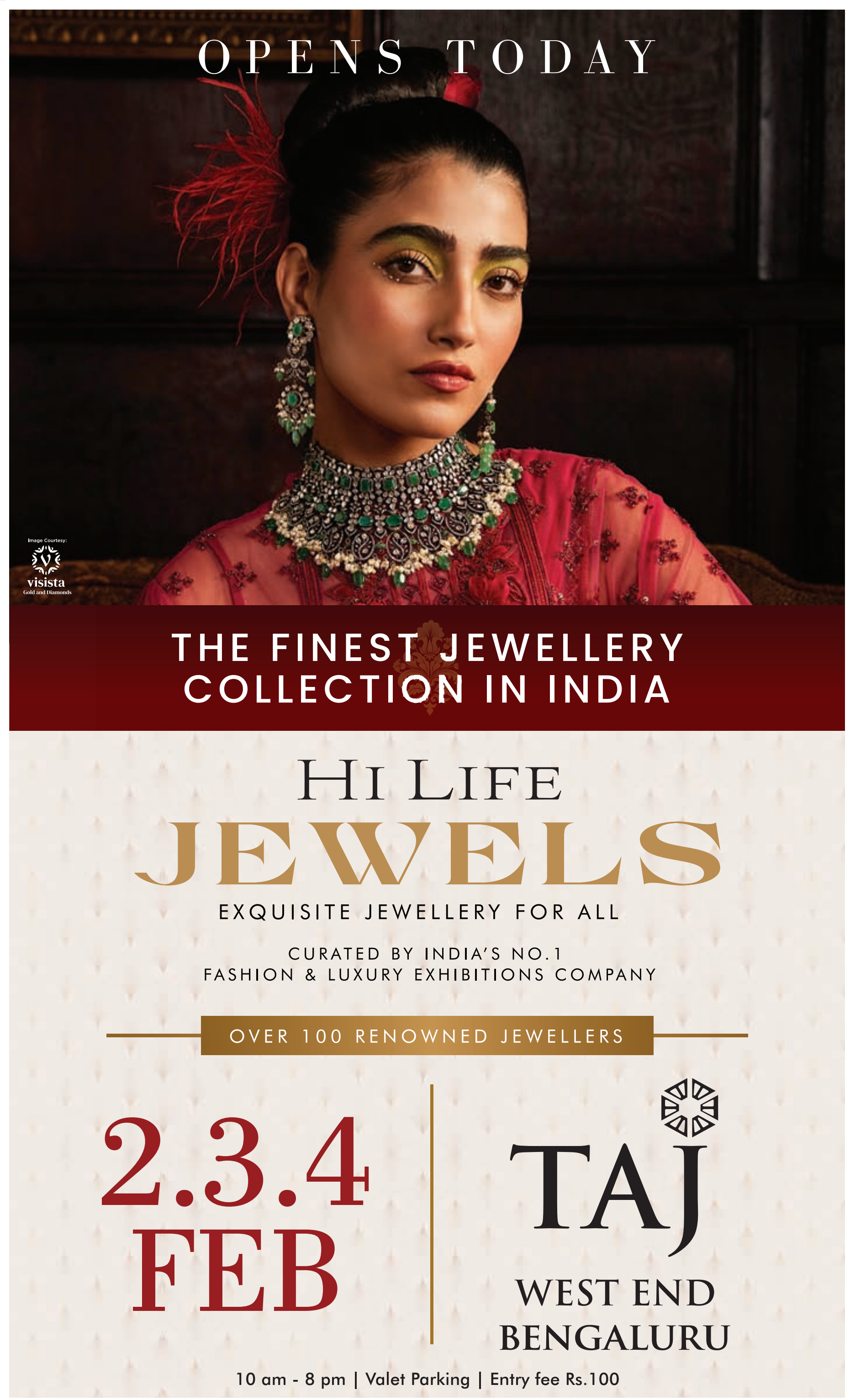

वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट

खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाएगी और डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी।

खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है। विपणन वर्ष 2022-23 (नवंबर-अक्टूबर) के दौरान, देश ने लगभग 165 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया, जिसका मूल्य 1.38 लाख करोड़ रुपए था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण स्तर और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। एक प्रमुख उर्वरक, नैनो-तरल डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) के अनुप्रयोग को सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी।

सीतारमण ने कहा, किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं। हर साल, पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत, सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। ये कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा, देश और दुनिया के लिए भोजन पैदा करने में 'अन्नदाता' की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्च विकास और उत्पादकता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन्हें किसान-केंद्रित नीतियों, आय सहायता, मूल्य और बीमा समर्थन के माध्यम से जोखिमों के 'कवरेज' और स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने की सुविधा मिल रही है।

घरेलू मांग को पूरा करने के मकसद से खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अंतरिम बजट में यह भी प्रस्ताव है कि तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाई जाएगी।

सीतारमण ने कहा, वर्ष 2022 में घोषित पहल पर आगे बढ़ते हुए, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के मामले में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक खेती तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्यवर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर, 2023 में समाप्त हुए चालू तेल वर्ष में देश का वनस्पति तेल आयात 16 प्रतिशत बढ़कर 167.1 लाख टन हो गया। इससे पिछले तेल वर्ष 2021-22 (नवंबर-अक्टूबर) में भारत ने 144.1 लाख टन वनस्पति तेल का आयात किया था।

मूल्य के संदर्भ में, एसईए ने कहा कि देश का खाद्य तेल आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 1.38 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2021-22 के 1.57 लाख करोड़ रुपए से कम है। वित्त मंत्री ने कहा कि डेयरी किसानों के समर्थन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा, खुरपका और मुंहपका जैसी बामारियों को नियंत्रित करने के प्रयास पहले से ही जारी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफल करते हुए परिणामदायी बनाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने जोर दिया कि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना ने 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और साठ हजार व्यक्तियों को 'क्रेडिट लिंकेज' से सहायता प्रदान की है। अन्य योजनाएं फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और उत्पादकता और आय में सुधार के प्रयासों को पूरक बना रही हैं।

सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए लड़कियों के टीकाकरण को बढ़ावा देगी सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-2025 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि वह देश में सर्वाइकल कैंसर के मामलों पर बारीकी से नजर रख रहा है और राज्यों तथा विभिन्न स्वास्थ्य विभागों के साथ नियमित संपर्क में है।

वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए 'सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया' के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदर पूनावाला ने कहा ''मैं सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों के टीकाकरण की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत करता हूं। आइये, एचपीवी से बचाव का संकल्प लें और टीकाकरण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करें।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा ''आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाना, और मेडिकल कालेजों की स्थापना और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को व्यवस्थित करना स्वास्थ्य के लिए सरकार की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने पिछले साल मार्च में राज्यसभा को बताया था कि बीमारी के दबाव पर ताजा प्रमाण, एचपीवी टीके की एकल खुराक की प्रभावशीलता पर प्रमाण, क्लीनिकल परीक्षण के आंकड़े और टीके की शुरुआत पर सिक्किम सरकार के अनुभव के आधार पर, जून 2022 में टीकाकरण पर 'राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह' (एनटीएजी) ने एक सिफारिश की थी।

यह सिफारिश 9 से 14 साल की किशोरियों के लिए एक बार और इसके बाद नौ साल तक नियमित रूप से एचपीवी टीकाकरण को लेकर थी। एचपीवी टीका 'ह्यूमन पेपिलोमा वायरस' (एचपीवी) के संक्रमण के कारण होने वाले कुछ कैंसर से बचाता है जिनमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। दुनिया भर में महिलाओं की कुल आबादी का 16 फीसदी हिस्सा भारत में है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग एक चौथाई मामले और वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग एक-तिहाई मौत भारत में होती हैं।

अधिकारियों ने कहा था कि भारतीय महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम 1.6 प्रतिशत और सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु का जोखिम एक प्रतिशत है। कुछ हालिया अनुमानों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 80,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है और करीब 35,000 महिलाओं की इसके कारण मृत्यु हो जाती है। मेर्क शार्प एंड दोहमे की सहायक शाखा एमएसडी फर्मास्यूटिकल्स प्रा लि भारत में एचपीवी के टीके 'गर्डसिल 4' का विक्रय करती है जिसकी वर्तमान में प्रति खुराक कीमत 3,927 रुपए है।

कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो चालू वित्त वर्ष से थोड़ा अधिक है। बजट दस्तावेज़ के अनुसार, कृषि मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,27,469.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कृषि विभाग को 1,17,528.79 करोड़ रुपए मिलेंगे जबकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) को 9,941.09 करोड़ रुपए मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार, कृषि विभाग को 1,16,788.96 करोड़ रुपए जबकि डीएआरई को 9,876.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि विभाग के तहत प्रमुख पीएम-किसान योजना के लिए आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रहेगा। इस योजना के तहत सरकार किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान करती है।

सामाजिक न्याय मंत्रालय को मिले 14,225 करोड़ रुपए

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश अंतरिम बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 14,225.47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2023-24 के बजट (संशोधित अनुमान) के 11,078.33 करोड़ रुपए के मुकाबले 28.4 प्रतिशत अधिक है। अंतरिम बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को 2024-25 में 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग को 1,225.27 करोड़ रुपए मिले हैं।

'रूफटॉप' सौर संयंत्र के लिए 10,000 करोड़ रु. का प्रावधान

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी जिससे उन्हें सालाना 18,000 रुपए तक की बचत होगी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बजट पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, बजट में रूफटॉप सोलर (योजना) के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छतों पर सौर इकाई लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने में सक्षम होंगे।

जनगणना के लिए 1,277.80 करोड़ रुपए आवंटित

नई दिल्ली/भाषा। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में जनगणना के लिए 1,277.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2021-22 के आवंटन की तुलना में काफी कम हैं जब 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि तीन साल की देरी के बाद भी इस साल इसे कराए जाने की संभावना नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में 8,754.23 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना-2021 करने और 3,941.35 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को अद्यतन करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। जनगणना में आवास की सूची बनाने का चरण और एनपीआर को अद्यतन करने की कवायद 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक देश भर में की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई। सरकार ने अभी तक जनगणना के नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

विदेश मंत्रालय को मिला 22,154 करोड़ रु. का आवंटन

नई दिल्ली/भाषा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बृहस्पतिवार को संसद में पेश अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय (एमईए) को कुल 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले साल उसका परिव्यय 18,050 करोड़ रुपए था। भारत की 'पड़ोस पहले' नीति के अनुरूप, 2,068 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 'सहायता मद' का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को दिया गया है। 2023-24 में हिमालयी राष्ट्र के लिए विकास परिव्यय 2,400 करोड़ रुपए था। ईरान के साथ संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाओं पर भारत के फोकस को रेखांकित करते हुए, चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपए ही रखा गया है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, मालदीव की विकास सहायता पिछले साल के 770 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल 600 करोड़ रुपए रखी गई है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंध कायम रखते हुए, उसके लिए 200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। बांग्लादेश को विकास सहायता के तहत 120 करोड़ रुपए जबकि नेपाल को 700 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। बजट दस्तावेजों के अनुसार, श्रीलंका को 75 करोड़ रुपए की विकास सहायता मिलेगी जबकि मॉरीशस के लिए 370 करोड़ रुपए तथा म्यांमा के लिए 250 करोड़ रुपए की विकास सहायता राशि तय की गई है।

खेल मंत्रालय के बजट में 45 करोड़ रुपए का इजाफा

नई दिल्ली/भाषा। खेल मंत्रालय को गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में 3,442.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जिसमें पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। पिछले बजट में खेल मंत्रालय को 3,396.96 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। इस 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान देश का मुख्य ध्यान पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेल पर लगा होगा। खेलों इंडिया को पिछले बजट में 20 करोड़ रुपए का इजाफा कर 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रीय शिविर आयोजित करने वाले, खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचा और उपकरण मुहैया कराने वाले और कोचों की नियुक्ति के अलावा अन्य काम करने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के बजट में पिछले साल की तुलना में 26.83 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई जिससे अब यह 795.77 करोड़ रुपए का होगा। राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के 2023-24 के 325 करोड़ रुपए बजट में इस दफा 15 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया।

नमो भारत व मेट्रो रेल शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक : वित्त मंत्री

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में तीव्र शहरीकरण हो रहा है और नमो भारत ट्रेन एवं मेट्रो रेल आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यन्त तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'ट्रांजिट' आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में देश के पहले 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (आरआरटीएस) को हरी झंडी दिखाई थी। उसका नाम नमो भारत ट्रेन रखा गया है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, देश में प्रति दिन करीब एक करोड़ यात्री मेट्रो ट्रेन की सवारी कर रहे हैं।

देश में मेट्रो प्रणालियों की लंबाई करीब 20 शहरों में 895 किलोमीटर से अधिक है और विभिन्न शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो सेवाएं निर्माणाधीन हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत) गलियारे का 17 किलोमीटर लंबा हिस्सा चालू हो गया है। गाजियाबाद के दुहाई डिपो से मेरठ साउथ तक 25 किलोमीटर लंबे हिस्से के दो महीने में चालू होने का अनुमान है।

'40,000 डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा'

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा और तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप, अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ तीन आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों से जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे जिनमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्क गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे शामिल हैं।

रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जबकि पिछले साल यह आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही सरकार ने सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश अंतरिम केंद्रीय बजट में, पूंजीगत व्यय के लिए सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदना शामिल है। पिछले साल यानी 2023-24 में पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपए था।

वित्त मंत्री ने कहा, रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। बजट दस्तावेज के अनुसार, कुल राजस्व व्यय 4,39,300 करोड़ रुपए आंका गया है जिनमें रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए, रक्षा सेवाओं के लिए 2,82,772 करोड़ रुपए और रक्षा मंत्रालय (नागरिक) के लिए 15,322 करोड़ रुपए शामिल हैं। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय में, विमान और एयरो इंजन के लिए 40,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य साजोसामान के लिए 62,343 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही नौसेना बेड़े के लिए 23,800 करोड़ रुपए और नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं के लिए 6,830 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में, भारतीय वायु सेना के लिए पूंजी परिव्यय सबसे अधिक 57,137.09 करोड़ रुपए था, जिसमें विमान और एयरो इंजन की खरीद के लिए 15,721 करोड़ रुपए और अन्य साजोसामान के लिए 36,223.13 करोड़ रुपए शामिल थे।

अंतरिम बजट में थल सेना के लिए राजस्व व्यय 1,92,680 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि नौसेना और वायु सेना को क्रमशः 32,778 करोड़ रुपए और 46,223 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय को 98,418 करोड़ रु का आवंटन, जल जीवन मिशन के लिए सर्वाधिक धन

नई दिल्ली/भाषा। जल शक्ति मंत्रालय को 2024-25 के अंतरिम बजट में 98,418 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसमें 71 प्रतिशत हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में मंत्रालय का बजट 96,549 करोड़ रुपए था।

पेयजल और स्वच्छता विभाग को बजट में 77,390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2023-24 से 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। इसमें से जल जीवन मिशन का हिस्सा 69,926 करोड़ रुपए है। मिशन का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। मिशन के तहत अब तक देश के 19.26 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.22 करोड़ को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग को 21,028 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों से संबंधित राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

जीएसटी संग्रह बढ़ने से सकल कर राजस्व 38.31 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार का सकल कर राजस्व अगले वित्त वर्ष में 11.46 प्रतिशत बढ़कर 38.31 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसे माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि से प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते समय संशोधित बजट अनुमानों की जानकारी दी। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह बढ़कर 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 1.1 लाख करोड़ रुपए यानी 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अगले वित्त वर्ष के कुल कर संग्रह में से 21.99 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर (व्यक्तिगत आयकर एवं कॉरपोरेट कर) और 16.22 लाख करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी) से आने का अनुमान है। वहीं चालू वित्त वर्ष में सरकार का अनुमान है कि सकल कर राजस्व बजट अनुमान से लगभग 76,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। चालू वित्त वर्ष के बजट में कर राजस्व 33.61 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया था। लेकिन अंतरिम बजट 2024-25 में इसे संशोधित कर 34.37 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। कॉरपोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के अनुरूप ही रहा है लेकिन चालू वित्त वर्ष में व्यक्तिगत आयकर संग्रह बजट अनुमान से 1.20 लाख करोड़ रुपए अधिक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क संग्रह का संशोधित अनुमान भी बढ़ाकर क्रमशः 2.19 लाख करोड़ रुपए एवं 3.08 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी प्राप्तियां 9.57 लाख करोड़ रुपए के बजटीय स्तर पर रहने का अनुमान है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
बेंगलूरु क्लासीफाइड
उपलब्ध
DNR Highline @ Okalipuram
near LULU Mall Rajajinagar
3 & 4 BHK FLATS
with 7 Star Luxurious Amenities.
Only Few Flats available for Sale.
for details
Contact Owner: 9844027560

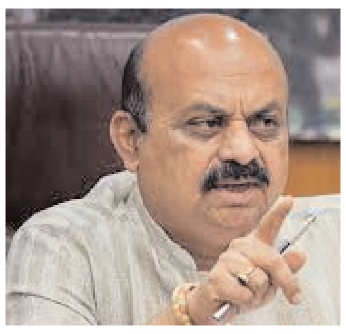

भाजपा नेताओं बोम्मई, येडीयुरप्पा और विजयेंद्र ने की अंतरिम बजट की सराहना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई,भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा और पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा ने गुरुवार को संसद में पेश अंतरिम बजट की सराहना की। बोम्मई ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया 2024-25 का अंतरिम बजट भारत के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सपने को पूरा करने के लिए सही दिशा में जा रहा है।

उन्होंने अपने एक्स एकाउंट पर लिखा, यह एक बहुत ही साहसिक और उज्वल बजट है जो देश को पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए सही दिशा में ले जा रहा है, जो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है।

बोम्मई ने कहा, यह पिछले नौ वर्षों की एक मजबूत आर्थिक तस्वीर प्रदान करता है। भले ही यह एक अंतरिम बजट है, यह पिछले नौ वर्षों की एक मजबूत आर्थिक तस्वीर प्रदान करता है। एफडीआई में वृद्धि, रोजगार दर में वृद्धि और जन कल्याण योजनाओं में वृद्धि। यह समावेशी विकास और आर्थिक विकास के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी विकास और आर्थिक विकास के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है और विकासोन्मुख है, जिसमें एक बार फिर बुनियादी ढांचे, गरीबों के लिए आवास, किसान कार्यक्रमों के लिए अधिक धन और महिला-उन्मुख विकास पर जोर दिया गया है। बोम्मई ने कहा कि बजट करदाताओं के लिए भी राहत प्रदान करता है और राज्य को कुछ सुधारों के साथ शून्य प्रतिशत ब्याज या 50 वर्षों में देय 1.5 लाख करोड़ रुपये की पेशकश करके अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है।

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने कहा कि अगले मील के पत्थर के लिए एक मजबूत भारत के निर्माण की भव्य महत्वाकांक्षा, संसद में पेश किया गया बजट एक ऐसे भारत के निर्माण की योजना बनाने का विश्वास जगाने वाला वादा है जो 2047 तक दुनिया में सबसे आगे खड़ा होगा। श्री येडीयुरप्पा ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी बजट है, जिसका लक्ष्य देश में कृषि, परिवहन, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर जोर देकर विकसित भारत के सपने को साकार करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बेहतरीन बजट पेश किया है जो देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करेगा और नये भारत के निर्माण की महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा। जनता को आशा देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडीयुरप्पा ने इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और पीएम मोदी की नवभारत की संकल्पना को साकार करने वाला प्रगतिशील बजट बताया। उन्होंने कहा, बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और विशेष रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, जिससे नई आशा और अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, 'चुनाव पूर्व लोकप्रिय नारों वाला बजट पेश किए बिना इस अंतरिम बजट के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री ने यथार्थवादी बजट पेश किया है। इस बजट ने आने वाले दिनों में एक मजबूत, सशक्त, विकसित, विश्व-गुरु भारत के निर्माण के प्रति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।'

लोकसभा चुनाव

पार्टी संस्थापक रामदास गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) की विशेष आम परिषद की बैठक में गुरुवार को पार्टी संस्थापक डॉ. एस. रामदास को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को अंतिम रूप देने पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। यहां आयोजित बैठक में इस आशय का एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि दो महीने में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा इस महीने के अंत तक होने की संभावना है।इसमें कहा गया है कि पीएमके ने राज्य और देश की चिंता और कल्याण करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव का सामना करने का फैसला किया है।

प्रस्ताव में कहा गया, बैठक डॉ. रामदॉस को यह तय करने के लिए अधिकृत करती है कि चुनाव का सामना करने के लिए किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है। पीएमके ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन के हिस्से के रूप में 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ा था। जिसमें अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषगम, भारतीय जनता पार्टी, डीएमडीके, तमिल मनीला कांग्रेस और पुथिया तमिझागम शामिल दल थे।इस मोर्चे को करारी हार का सामना करना पड़ा और केवल अन्नाद्रमुक ने अकेले ही एक सीट (थेनी निर्वाचन क्षेत्र) जीती। पीएमके ने गठबंधन के तहत सात सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी।

द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने कांग्रेस,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी , वीसीके, एमडीएमके, आईयूएमएल, के साथ कुल 40 सीटों में से 39 (तमिलनाडु में 39 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एकमात्र सीट) जीतकर शानदार जीत हासिल की।

कर्नाटक भाजपा ने 'दक्षिण भारत अलग राष्ट्र' वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद की आलोचना की

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद डीके सुरेश की दक्षिण भारत अलग राष्ट्र' वाली टिप्पणी और कथित तौर पर भारत को विभाजित करने के लिए उनकी आलोचना की। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ सांसद और केपीसीसी प्रमुख डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने भारत तोड़ो का आह्वान किया। यह कांग्रेस की वही मानसिकता है, जिसके कारण विभाजन हुआ। आर. अशोक ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से यह भी पूछा कि यदि एक निर्वाचित सांसद जिसने संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की शपथ ली है।

अंतरिम बजट प्रगतिशील, लोगों के जीवनस्तर में सुधार करेगा : येडीयुरप्पा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट को 'प्रगतिशील' करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बीएस येडीयुरप्पा ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह बजट लोगों के जीवनस्तर के मानकों को ऊंचा करेगा।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट आने वाले दिनों में 'एक मजबूत, सशक्त, विकसित और विश्वगुरू' भारत के निर्माण के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है जो देश की प्रगति का पूरक है।

येडीयुरप्पा ने 'एक्स' पर लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल से बधाई जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए देश का प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नवभारत की अवधारणा को पूरा करने की दिशा में काम किया है।

उन्होंने कहा, ''अंतरिम बजट होते हुए भी वित्त मंत्री ने चुनाव पूर्व लोक-लुभावने नारों के बिना बजट पेश किया। उन्होंने एक यथार्थवादी बजट प्रस्तुत किया है जो हमारे युवाओं, किसानों, महिलाओं और विशेष रूप से समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों के जीवनस्तर को सुधारेगा और नई उम्मीद एवं अवसर पैदा करेगा।''

हनुमान ध्वज हटाने का विवाद कर्नाटक के अन्य हिस्सों में भी फैला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, भाजपा और हिंदू संगठनों के बीच विवाद का मुद्दा बना हनुमान ध्वज हटाने का मामला अब धीरे-धीरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है। मंड्या जिले में एक सार्वजनिक स्थान से हनुमान ध्वज हटाए जाने के बाद कई कस्बों में सार्वजनिक स्थानों पर हरे झंडे लगाए गए।

चिक्कबल्लापुर शहर के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को डोड्डाभजामे माने इलाके के पास एक ध्वज स्तंभ पर फहराए गए हरे झंडे को हटाने के लिए अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की है। नगर निगम अधिकारियों ने मौके का दौरा किया था और संबंधितों को झंडा हटाने का निर्देश दिया था।

भाजपा नेताओं ने कोलार शहर के प्रसिद्ध घंटाघर पर स्थापित आधे चांद और स्टार वाली संरचना को हटाने की मांग की है। कोडागु-मैसूरु के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने भी अधिकारियों से मैसूरु शहर में हरा झंडा हटाने का आग्रह किया है।

प्रताप सिम्हा ने सरकार से सवाल किया था, ''क्या आपको मैसूरु शहर के कैलासपुरम में अंबेडकर पार्क के पास हरा झंडा नहीं दिख रहा है? आपने एक झंडा क्यों हटा दिया और दूसरे को यहां रहने दिया?''

विवाद के बाद अधिकारियों ने बेंगलूरु के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शिवाजी नगर के चांदनी चौक पर हरा झंडा हटा दिया था और राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इस बीच, बजरंग दल के सूत्रों ने कहा कि वे जिले में शुक्रवार से हनुमान ध्वज अभियान शुरू करेंगे। इससे पहले, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने घोषणा की थी कि पूरे राज्य में केसरिया झंडा अभियान चलाया जाएगा, जहां सभी घरों पर झंडे फहराए जाएंगे।

समाना मनस्करा वेदिके ने 7 फरवरी को मंड्या में बंद का आह्वान किया है। वहीं, बजरंग दल ने हनुमान ध्वज हटाए जाने की निंदा करते हुए 9 फरवरी को मांड्या जिले में बंद का आह्वान किया है। बीजेपी इकाई ने हाल ही में राज्यव्यापी बंद भी किया था। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मांड्या जिले के केरागोडु गांव में जहां से विवाद शुरू हुआ था, वहां 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। गांव में धारा 144 जारी रहेगी।

प्रदर्शन

बेंगलूरु में गुरुवार को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) के सदस्यों ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए।

एक व्यक्ति ने पत्नी को 12 साल तक हिरासत में रखा, पुलिस ने बचाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में एक चौंकाने वाली घटना में, मैसूरु जिले के हिरेगे गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके चरित्र के संदेह में 12 साल तक घर में नजरबंद रखा। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार रात घर पर छापा मारा और पीड़िता सुमा को बचाया और आरोपी सन्नालैया को भी गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुमा आरोपी की तीसरी पत्नी है। शादी के दिन से ही वह उस पर शक कर रहा था। शादी के पहले सप्ताह में, उसने उसे अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। कथित तौर पर उसकी यातनाओं को सहन करने में असमर्थ पहली दो पत्नियों ने आरोपी को छोड़ दिया था। पति ने दरवाजे पर तीन ताले लगा दिए और पत्नी को किसी से बात न करने की चेतावनी दी।

उसने उसे घर के बाहर स्थित शौचालय का उपयोग करने से भी मना किया। आरोपी ने इसके लिए कमरे के अंदर एक बाल्टी रखी थी और उसे खुद ही डिस्पोज करता था। इससे आहत पीड़िता के एक रिश्तेदार ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया था। एएसआई सुभान, वकील सिद्दप्पाजी और सामाजिक कार्यकर्ता जशीला की टीम ने घर पर छापा मारा और पीड़िता को बचाया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को धमकी दी थी कि अगर वह घर से बाहर निकली या किसी से बात करने की कोशिश की, तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा।

हालांकि पीड़िता की मां ने समाधान खोजने के लिए स्थानीय नेताओं से संपर्क किया, लेकिन आरोपी नहीं माना और अपनी क्रूरता जारी रखी। आरोपी से पीड़िता के दो बच्चे हैं, जिन्हें अब उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया है। पीड़िता सुमा ने बताया, मेरे पति ने मुझे बंद कर दिया और मुझे अपने बच्चों से खुलकर बात नहीं करने दी। वह बिना किसी कारण के मुझे बार-बार थप्पड़ मारता था। गांव के सभी लोग उससे डरते हैं। देर रात घर आने तक वह मेरे बच्चों को मेरे साथ नहीं रहने देता था। मुझे उन्हें छोटी खिड़की से खाना देना पड़ता था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।

कुमारस्वामी ने बजट की सराहना की

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। जनता दल एस (जदएस) के नेता एच डी कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट को 'जनोन्मुखी, विकासोन्मुखी और प्रगतिशील' बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट उन कार्यक्रमों के संकेत देता है, जिन्हें लोकसभा चुनाव के बाद पेश किये जाने वाले पूर्ण बजट में जगह मिल सकती है। उन्होंने खासकर कृषि के संबंध में किये गये आवंटन का उल्लेख किया।

कुमारस्वामी ने कहा, ''मैं खुश हूं कि बजट में विभिन्न तिलहनों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रावधान है। इससे देशभर के किसान लाभान्वित होंगे। संग्रह, भंडारण, विपणन , ब्रांडिंग आदि के लिए कृषि केंद्रित बुनियादी ढांचों के विकास पर बल दिया जाना एक स्वागतयोग्य कदम है।''

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम
पता: प्रथम एवं द्वितीय तल, एकेपी रत्ना टावर, नं. 13,भारतियार स्ट्रीट सुब्रमनिया नगर सूरमंगलम, सेलम, तमिलनाडु – 636005. दूरभाष: 0427-2334811. ईमेल:smpndrosalem@unionbankofindia.bank

पट्टे पर परिसर की आवश्यकता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को धर्मापुरी शाखा के लिए फोर रोड्स जंक्शन, अधियमान बाई पास रोड, धर्मापुरी से 500 मीटर की परिधि के अंदर 1400 ± 10% वर्गफुट के कार्पेट क्षेत्र में एक अच्छी तरह से निर्मित "कब्जे के लिए तैयार" या "निर्माणाधीन" वाणिज्यिक परिसर या "हमारे विनिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए मालिक की प्रतिबद्धता के साथ खाली भूखंड" की आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से भूतल पर अच्छा अग्रभाग ,मुख्य सड़क तक आसान पहुँच, पर्याप्त पार्किंग सुविधा और और धर्मापुरी शाखा के लिए बैंक की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएं हों.

क्र.सं.	शाखा	आवश्यक कार्पेट क्षेत्रफल	स्थान
1	धर्मापुरी	1400 ± 10%	फोर रोड्स जंक्शन, अधियमान बाई पास रोड, धर्मापुरी से 500 मीटर की परिधि के अंदर

मालिकाना हक प्राप्त प्रत्याशित विक्रेता या मालिकों की ओर से बातचीत का अधिकार रखने वाले दिनांक 02/02/2024 से कार्यालय अवधि के दौरान (सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम के उपरोक्त पते से तकनीकी बोली/ मूल्य बोली का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं या www.unionbankofindia.co.in (या) eprocure.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्ताव को अलग लिफाफों में "तकनीकी बोली और मूल्य बोली" लिखकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, # एकेपी रत्ना टावर, 13,भारतियार स्ट्रीट, सुब्रमनिया नगर, सूरमंगलम, सेलम, तमिलनाडु – 636005 पर दिनांक 16/02/2024 को या उससे पहले शाम 4:00 बजे तक भेज सकते हैं. बोलियों को विक्रेता/ उनके प्रतिनिधियों के उपस्थिति में दिनांक 16/02/2024 को शाम 4:30 बजे उपरोक्त लिखे पते पर खोला जाएगा. प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों जैसा की वेंडर प्रमाणन में निर्दिष्ट है, पर विचार नहीं किया जाएगा. किसी भी दलाल या बिचौलिये के साथ बातचीत नहीं की जाएगी. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी/ अर्ध-सरकारी निकायों द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली संपत्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी भी परस्थिति में कार्यालय परिसर हेतु किसी अनधिकृत निर्माण पर विचार नहीं किया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in (या) eprocure.gov.in पर जाए, निर्धारित प्रारूप में बोलियों को जमा करने की अंतिम तिथि 16/02/2024 को शाम 4:00 बजे तक है.

बैंक बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

दिनांक : 01.02.2024 क्षेत्र प्रमुख

उपमुख्यमंत्री ने बजट की आलोचना कर कहा-

हम सभी भारत माता की संतान, हमें साथ रहना है

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। भारत को विभाजित करने पर अपने भाई और कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश की टिप्पणियों पर सवालों का जवाब देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को कहा मैं अखंड भारत का नागरिक हूं। सुरेश ने आज घोषित अंतरिम बजट में राजस्व का उचित हिस्सा नहीं मिलने को लेकर लोगों की निराशा को ही दर्शाया है। हम सब भारत माता की संतान हैं और हमें मिलकर रहना है। दक्षिण भारत को भी वही प्राथमिकता और महत्व मिलना चाहिए जो हिंदीभाषी राज्यों को दिया जाता है।

शिवकुमार ने अंतरिम बज ट को अब तक का सबसे खराब बजट बताया और कहा कि कर्नाटक को एक कच्चा सौदा मिला है। उन्होंने कहा, कर्नाटक ने 26 भाजपा सांसदों को चुना है और अब यह संख्या 27 हो गई है। सभी सांसदों ने कर्नाटक के लिए क्या किया है? क्या कर्नाटक के भाजपा सांसद कम से कम अब संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिवकुमार ने कहा, 'मैंने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और कर्नाटक की विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटन की अपील की थी, लेकिन कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है। कई सिंचाई परियोजनाएं धन की कमी के कारण पीड़ित हैं और बेंगलुरु में कई नई परियोजनाओं को धन की जरूरत है। वह कर्नाटक से चुनी गई हैं, लेकिन बजट में कर्नाटक को एक कच्चा सौदा मिला है।

उन्होंने कहा, मैंने बेंगलूरु में विकास कार्यों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। पिछले बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए घोषित 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस बजट से कर्नाटक को कुछ नहीं मिला, यह बेहद निराशाजनक बजट है।

मेकेदातु पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा,आज कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक है और हमने अपने अधिकारियों को भेजा है। हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद गारंटी बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारी गारंटी योजनाएं पूरे पांच साल तक जारी रहेंगी और यह हमारी प्रतिबद्धता है। हम अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस आएंगे और गारंटी योजनाएं जारी रखेंगे।

दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय अलग राष्ट्र की मांग को मजबूर कर सकता है : डी के सुरेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद डी के सुरेश ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर विभिन्न करों से एकत्रित धनराशि के वितरण के मामले में दक्षिणी राज्यों के साथ हो रहे 'अन्याय' को ठीक नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डी के सुरेश ने यह दावा किया कि दक्षिण से एकत्रित कर की धनराशि को उत्तर भारत में वितरित किया जा रहा है और दक्षिण भारत को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।

सुरेश के भाई और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि सुरेश ने केवल आम जनता की धारणा के बारे में बात की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सुरेश के इस बयान को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। सुरेश के इस बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने कहा, दक्षिण भारत के लिए अलग राष्ट्रीयता की मांग नहीं की जा सकती। देश की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए। हालांकि, सिद्दरामैया ने कहा कि कर हस्तांतरण को लेकर दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। बेंगलूरु ग्रामीण सीट से सांसद सुरेश ने दावा किया कि दक्षिणी राज्यों से एकत्र कर को उत्तर भारत में वितरित किया जा रहा है और हर दृष्टि से दक्षिण भारत पर 'हिंदी थोपी'' जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश ने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि अगर केंद्र कर्नाटक को उसके हिस्से का पैसा दे दे तो यह पर्याप्त होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी मांग है कि हमें अपने राज्य से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष करों में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हम दक्षिण भारत के साथ बहुत अन्याय होते हुए देख रहे हैं... हम अपने हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटते हुए देख रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण भारत के साथ सभी पहलुओं में अन्याय हुआ है। सुरेश ने कहा, अगर आज हम इसकी निंदा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के लिए एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखने की नौबत आ जाएगी। सुरेश की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि उनके भाई ने केवल सार्वजनिक धारणा के बारे में बात की है। शिवकुमार ने कहा, 'मैं अखंड भारत का हूं। भारत एक है। सुरेश ने सिर्फ लोगों के विचार व्यक्त किये हैं। लोग सोच रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बात की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है। कहीं भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे सुदूरवर्ती गांव को भी हिंदी पट्टी के क्षेत्रों जैसा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।' सिद्दरामैया ने कहा, 'कर संग्रह के मामले में हम (कर्नाटक) देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इसके बावजूद, हमारे साथ अन्याय हो रहा है।' भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने सुरेश की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को बोलने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए।

इसरो isro
भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष, अनुसंधान संगठन
(निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग)
इसरो टेलिमेट्रि ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक)
प्लाट नं. 12 एवं 13, तीसरा मेन, द्वितीय फेज, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु-560058
फैक्स : 080-28094180 फोन : 080-28094182, 4541

संशोधन -1 दिनांक : 01.02.2024

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, समुचित वर्ग के ठेकेदरों से एनआईटी में निम्न लिखित कार्यों के लिए नग दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

एनआईटी सं	इस्ट्रैक/सीएमजी/ई/एमएआईएनटी/ईटीएन-83 2023-2024 दिनांक 11.01.2024
कार्य का नाम	बेंगलूरु के ब्याललु गांव के आईडीएसएन परिसर में विभिन्न इमारतों में यूपीएस के लिए बैकअप आपूर्ति के रूप में स्थापित एक्ससिड की प्लांट बैटरियों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध।
निविदा का अनुमानित मूल्य	रु. 18.83 लाख
निविदा दस्तावेज विवरण	ई-निविदा
कार्य समापन अवधि	बारह (12) माह/विभाग के पास कार्य अनुबंध को आगे 24 माह तक बढ़ाने का अधिकार है।
निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि	12.01.2024 को 16.00 बजे से 26.01.2024 को 16.00 बजे तक जिसे 07.02.2024 तक बढ़ाया गया ।
बोली स्पष्टीकरण	13.01.2024 को 16.00 बजे से 27.01.2024 को 16.00 बजे तक जिसे 08.02.2024 तक बढ़ाया गया ।
बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख	29.01.2024 को 16.00 बजे तक जिसे 09.02.2024 तक बढ़ाया गया ।
निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	30.01.2024 को 16.00 बजे तक जिसे 09.02.2024 तक बढ़ाया गया ।
निविदा खोलने की नियत तारीख और समय	01.02.2024 को 11.00 बजे से जिसे 12.02.2024 तक बढ़ाया गया ।
ईएमडी	रु. 37,660/-

पात्रता मानदंड और अन्य ब्यौरे के लिए इच्छुक निविदाकार विस्तृत सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी) देंखे जिसे वेबसाइट www.isro.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली प्रपत्र औप अन्य ब्यौरे वेबसाइट www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ह/- समूह प्रमुख- सीएमजी

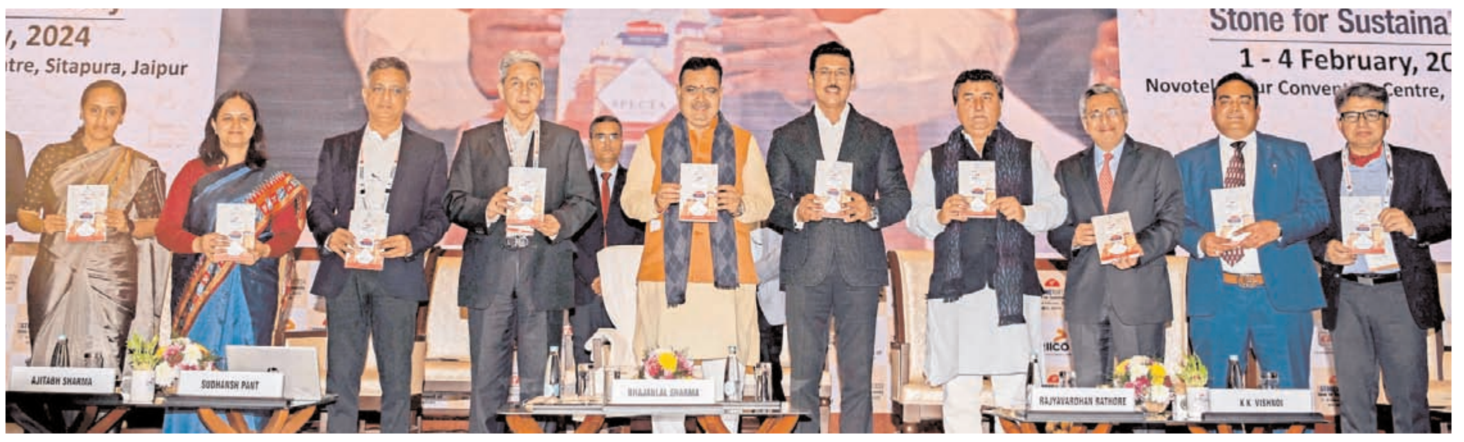

पत्थर उद्योग से राज्य में 10 लाख लोगों को मिल रहा है रोजगार : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर उद्योग समिट का आयोजन किया जाएगा जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें। शर्मा गुरूवार को जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोनमार्ट के 12 वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को विभाग से जुड़ी सभी क्लियरेंस एक ही छत के नीचे देने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम को अब प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राज्य में निवेश के लिए आगे आएं, राज्य सरकार उद्यमियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस भव्य मंदिर में राजस्थान का गुलाबी पत्थर तथा मार्बल उपयोग में लिया गया है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य में पत्थर उद्योग को विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने में इंडिया स्टोनमार्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राज्य का पत्थर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है तथा इसकी आपूर्ति राज्य के उद्यमियों द्वारा भरपूर फलीभूत की जा रही है। शर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट को रिसाइकल करना बहुत आवश्यक है। इस तरह के वेस्ट को उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसा की वर्तमान में किशनगढ़ मार्बल की स्लरी का उपयोग उद्योग के रूप में किया गया। उन्होंने उद्योग की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि जिस भी स्थान पर उद्योग लगाया जाता है वहां पर न केवल वहां कार्य कर रहे लोगों बल्कि आस पास के सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिससे वहां आर्थिक समृद्धि फैलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जहां राज्य मार्बल तथा सेंडस्टोन के लिए जाना जाता था, पर कुछ दशकों से राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पत्थर उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा राज्य में पत्थर उद्योग से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगले 5 साल में पत्थर उद्योग में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने का विभाग ने संकल्प लिया है। उन्होंने उद्यमियों की तारीफ करते हुए कहा कि 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को कारीगरों द्वारा ही साकार किया जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पत्थर उद्योग के साथ नव्यकरणीय ऊर्जा, जवाहरात, खनन सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें सरकार द्वारा और अधिक विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंटीरियर डिजाइनिंग, लैण्डस्केपिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों, लाइफटाइम अचीवमेन्ट अवॉर्ड से उद्यमी किरण जे त्रिवेदी तथा यशवंत कुमार शर्मा को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इंडिया स्टोनमार्ट निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोनमार्ट का फीता काटकर उद्घाटन एवं आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

सभी वर्गों के उत्थान का सर्व स्पर्शी बजट : जोशी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को शानदार करार देते हुए इसे सभी वर्गों के उत्थान का सर्व स्पर्शी बजट बताया। जोशी ने यहां एक बयान में कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और बजट में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप (खाका) पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, युवा अन्नदाता की जरूरतें एवं आकांक्षाए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि आमजन के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को सर्वस्पर्शी,समावेशी और गरीब कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला बजट बताया है।

दिलावर ने कहा कि बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य स्पष्ट नजर आता है। आगामी 5 वर्षों में दो करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंतरिम बजट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें राजस्थान को कुछ नहीं दिया गया।

उन्होंने मीडिया से कहा, 'अंतरिम बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं, किसी वर्ग को कोई सौगात नहीं।' डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'महंगाई कम करना इनका उद्देश्य नहीं है.. . बेरोजगारों को रोजगार देना इनका उद्देश्य नहीं है.. बिजली, पानी,सड़क, चिकित्सा कैसे ठीक हो यह इनका उद्देश्य नहीं है... इनको तो धर्म के नाम पर लड़ाना है और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करना है लोगों को डराना है, धमकाना है और परेशान करना और सत्ता पर बरकरार रहना है।'

जेएलएफ राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा : दीया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने में जयपुर साहित्य महोत्सव (जेएलएफ) के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पांच दिवसीय यह उत्सव पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पूरे वर्ष किए जाने वाले प्रयासों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जेएलएफ के उद्घाटन के अवसर पर दीया कुमारी ने कहा कि इस साहित्य उत्सव ने 'गुलाबी शहर' को विश्व मानचित्र पर ला दिया है।

गुलाबी नगरी में बृहस्पतिवार को थोड़ा तेज धूप के साथ क्लार्क्स आमेर होटल में दुनियाभर से आए साहित्यप्रेमियों और 500 से अधिक वक्ताओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, आपने (जेएलएफ) जयपुर को विश्व मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया है, यह हमेशा से वहां था लेकिन आपने इसमें और योगदान दिया... न केवल आप सभी के लिए,जो साहित्य जगत से जुड़े हैं, यह पर्यटन और सरकार के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन है।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपके प्रयास, पर्यटन उद्योग के लिए हममें से किसी के भी प्रयासों से कहीं अधिक हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग इस साहित्य उत्सव से जुड़ा है, लेकिन आप हर साल पांच दिनों में इसके (पर्यटन) लिए जितना करते हैं, वह हमारे प्रयासों से कहीं अधिक है ।

उपमुख्यमंत्री 2006 में इसकी शुरुआत से ही इस उत्सव से जुड़ी हुई हैं। उत्सव का उद्घाटन पारंपरिक रूप से लोकप्रिय राजस्थानी नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी और टीम द्वारा बजाई गई शंख ध्वनि के साथ हुआ और आयोजकों ने वादा किया कि तीन बुकर विजेताओं, पांच पुलित्जर विजेताओं और बैली गिफ़ोर्ड पुरस्कार के विजेता के साथ उत्सव अब तक के अपने 'सबसे भव्य' रूप में आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर, फेस्टिवल के निर्माता संजोय के रॉय ने जेएलएफ के पहले संस्करण के बाद से इसके 'चमत्कारी'सफर को रेखांकित किया । आयोजकों के अनुसार, जेएलएफ में पिछले साल करीब तीन लाख लोग आये थे । रॉय ने कहा, पहले आयोजन में प्रबंधकों ने कहा कि 230 सीटें हैं तो मेरा जवाब था कि, 'साहित्य उत्सव के लिए जयपुर कौन आएगा, 140 सीटें निकालो, 100 ही रखो।'

अब अजमेर में फॉयसागर से भी होगी जलापूर्ति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सख्ती के बाद जलदाय विभाग शहर की जलापूर्ति में सुधार को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने फॉयसागर झील से शहर को मीठे पानी की आपूर्ति की तैयारी शुरू कर दी है। गुरूवार को देवनानी ने स्वयं फॉयसागर रोड़ स्थित फिल्टर प्लांट पर जाकर सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमित जलापूर्ति और गर्मियों से पहले सम्पूर्ण पेयजल प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को अजमेर शहर एवं अजमेर उत्तर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने अजमेर में सर्किट हाऊस में आयोजित बैठक में पेयजल आपूर्ति में तत्काल सुधार एवं दीर्घकालिक प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इससे पूर्व उन्होंने फॉयसागर रोड़ फिल्टर प्लांट पर जाकर भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

देवनानी ने फॉयसागर झील से शहर में होने वाली जलापूर्ति की व्यवस्थाओं को स्वयं देखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया की पेयजल आपूर्ति का खाका इस तरह तैयार किया जाए कि प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि फॉयसागर से 3 एमएलडी पानी लिया जाएगा। इसे समान रूप से वितरित करने की योजना तैयार कर ली गई है।

देवनानी ने अधिकारियों से कहा कि जलापूर्ति में तत्काल सुधार के साथ ही भविष्य को देखते हुए भी योजना तैयार की जाए। इसके लिए अमृत योजना- फेज द्वितीय के तहत पूर्व में तैयार किये गये प्रस्तावों को पुनः तैयार किया जाए और उन्हें शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः डिजाइन किया जाए। यह प्रस्ताव भविष्य में अजमेर में उन्नत जल प्रबंधन की नींव साबित होगे।

देवनानी ने अधिकारियों से कहा कि शहर में लीकेज को तुरन्त सुधारा जाए एवं जलापूर्ति के समय सभी स्तर के अधिकारी स्वयं पेट्रोलिंग करे, ताकि यह पता लगे कि लीकेज कहा है। लीकेज का पता लगते ही उन्हें तुरन्त सुधारने की व्यवस्था की जाए।

नीतीश कुमार के राजग में जाने से विपक्षी गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा : पायलट

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने के कदम से विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को धार्मिक मुद्दों के बजाय केंद्र सरकार के दस वर्ष के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए।

पायलट ने टोंक में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए, 'यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार पाला बदल कर एक बार फिर भाजपा के साथ चले गये लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे गठबंधन 'इंडिया' का जो गठजोड है.. हमारा सीट-शेयरिंग है.. हम इकट्ठा चुनाव लड रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर सामने आये हैं उसमें कहीं कोई फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा हम पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।' टोंक से विधायक पायलट शादी समारोह में भाग लेने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा लगातार चल रही है और यात्रा को जो अपार समर्थन मिल रहा है उससे भाजपा भयभीत है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मार्मिक मुद्दे हैं.. जनता के मुद्दे हैं और उन्ही मुद्दों को जनता पसंद कर रही है।

प्रदेश के 13 जिलों मे कृषि-बागवानी को नई करवट देगी ईआरसीपी परियोजना : मीणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को ईआरसीपी के रूप में बड़ी सौगात दी है। हमें पानी खर्च करने में मितव्यता दिखानी होगी। वहीं, बूंद-बूंद पानी संचय के साथ-साथ सदुपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। कृषि मंत्री मीणा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में गुरूवार से शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन, सह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन, जल उपलब्धता 0.1 फीसदी के करीब है। जबकि, यहां भूमि की उर्वरता काफी अच्छी है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक और नई किस्मों को धरातल रूप देकर ना केवल किसानों की आय को बढाया जा सकता है। बल्कि, कृषि परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चंबल ऐसी नदी है, जिसमें पर्याप्त जलनिधी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा ईआरसीपी परियोजना के मंजूरी दिए जाने से अब पांच नदियां जोडक़र प्रदेश के 13 जिलों को पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्वी राजस्थान में बागवानी के साथ-साथ कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि संभव होगी। उन्होंने घटती कृषि जोत और उलपब्ध जल को देखते हुए किसानों से संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई और बागवानी से जुडऩे का आव्हन किया। साथ ही, रिसर्च को लैब से लैण्ड तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा तैयार 60 करोड़ लीटर क्षमता वाले वाटर रिसाईक्लिंग प्लांट की प्रशंसा की। साथ ही, शिखर सम्मेलन में आने वाले सुझावों को सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम को वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय, गोदावरी, आंधप्रदेश के कुलपति डॉ. टी जानकीराम ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से एआई, सेंसर और नैनो तकनीक को उपयोग में लाने पर जोर दिया। साथ ही, फूड इंडस्ट्रीज की मांग के अनुरूप प्रसंस्करण योग्य और पोषकता से भरपूर फल-सब्जी किस्मों के विकास की आवश्यकता जताई।

सम्मेलन में एसकेएनयू जोबनेर के कुलपति डॉ. बलराज सिंह ने देश-प्रदेश के बागवानी परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कलस्टर आधारित बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने 14 पाक विस्थापितों को प्रदान की नागरिकता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर जिला कलक्ट्रेट में गुरुवार को 52 वर्षीय जयवन्ती की आंखें उस वक्त छलक आई, जब कई सालों के इंतजार के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अतिरिक्त जिला कलक्टर अबू सुफियान चौहान ने 14 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण-पत्र सौंपे।

नागरिकता प्रमाण-पत्र मिलने के बाद सचानंद दास ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। वहीं, लाभार्थियों ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में उन्हें काफी असुविधा होती थी लेकिन अब भारतीय नागरिकता मिलने के बाद ना केवल उन्हें पहचान मिली है बल्कि अब सरकारी योजनाओं की मदद से वे अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जिला प्रशासन नागरिकता के आवेदनों पर प्राथमिकता से नियमानुसार कार्यवाही कर प्रमाण-पत्र जारी करता है ताकि आवेदक किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 294 पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

जैन श्रमणों के चातुर्मास के विहार के दौरान सुरक्षा, भूमि आवंटन के प्रस्ताव आमंत्रित

उदयपुर। राजस्थान सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार जैन संतों के चातुर्मास के लिये भूमि आवंटित करने एवं उन्हें पर्याप्त पुलिस संरक्षण प्रदान करने के संबंध में सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू की दी गयी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी खुशबू शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के दिशा-निर्देशानुसार इस संबंध में भूमि आवंटन के प्रस्ताव चाहे गये हैं। इस निमित्त राजस्थान राज्य में जैन श्रमणों के विहार भ्रमण एवं चातुर्मास के दौरान विहार, ठहरने एवं प्रवचनों आदि के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जिलों में विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटित करवायी जानी हैं। विभाग की ओर से जैन साधु साध्वियों के द्वारा आमतौर पर प्रयुक्त किये जाने वाले रूट को सूचीबद्ध करने, चातुर्मास में प्रवचन एवं विहार के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों के विवरण के साथ जैन श्रमणो के चातुर्मास के वास्ते उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान की अनुपलब्धता की स्थिति में सार्वजनिक भूमि भवन आवंटन के प्रस्ताव मांगे हैं।

संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को चुप कराने का केंद्र पर आरोप लगाया कांग्रेस ने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने बुधवार को भाजपा की केन्द्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराकर भाजपा की केंद्र सरकार सीबीआई, आयकर एवं प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सहयोग करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा 'डोनेट फॉर न्याय' अभियान को सफल बनाने के लिये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा एआईसीसी द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम राजस्थान की कांग्रेस को दिया गया है तो देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने ही किया है। उन्होंने कहा कि डोनेट फॉर देश कार्यक्रम में राजस्थान अव्वल रहा है तथा अब डोनेट फॉर न्याय अभियान में भी पूरे देश में राजस्थान प्रथम रहेगा।

अयोध्या के लिए दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई समेत आठ शहरों से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

योगी ने कहा कि इससे पर्यटन में भी वृद्धि होगी। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलूरु के लिए अयोध्या से वायु सेवा शुरू की जा चुकी है जो सफलतापूर्वक हो रही है संचालित

लखनऊ/भाषा। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रीरामलला के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अयोध्या पहुंचना अब और आसान हो गया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह ने आठ शहरों से अयोध्या आने-जाने के लिए स्पाइसजेट की सीधी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई, और बेंगलूरु से अयोध्या के लिए स्पाइसजेट द्वारा सीधी उड़ान सेवाएं शुरू होने से अयोध्या की हवाई संपर्क व्यवस्था और बेहतर हो गई है। बयान में कहा गया है कि इससे पर्यटन में भी वृद्धि होगी। इससे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और बेंगलूरु के लिए अयोध्या से वायु सेवा शुरू की जा चुकी है जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जब से श्रीरामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के हर नागरिक के चेहरे पर जो तेज है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वह एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यही ऊर्जा 2047 तक भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए स्पाइसजेट के मुख्य प्रबंध निदेशक अजय सिंह को भी धन्यवाद दिया और कहा कि समूह को उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रयासों को क्रांतिकारी बताया और कहा कि जहां राम का नाम होता है वहां सारे काम पूरे होते हैं।

धरना-प्रदर्शन मामले में एआईएमआईएम सांसद जलील के खिलाफ प्राथमिकी

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र)/भाषा। स्थानीय एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में यहां संभागीय आयुक्त कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किए जाने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद जलील ने दो दिन पहले यहां एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें मांग की गई थी कि सरकार आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक, जिसका लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था, और सात अन्य वित्तीय संस्थानों के खाताधारकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया में तेजी लाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने कहा धरना-प्रदर्शन के बाद जलील और अन्य के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, निचले इलाकों में बारिश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड के उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। हांलांकि, इससे कई सड़कें अवरुद्ध हो गईं।

बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, हेमकुंड साहिब की उंची पहाड़ियों में जमकर हिमपात हुआ जिससे वहां बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। बुधवार शाम से शुरू बर्फवारी के बाद बदरीनाथ में ढाई फीट तक बर्फ जम गई जबकि औली समेत ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होता रहा। प्रदेश के चमोली जिले में बदरीनाथ मोटर मार्ग हनुमान चट्टी से आगे बर्फवारी के कारण अवरुद्ध हो गया वहीं मंडल चोपता मोटर मार्ग धोती धार किलोमीटर 40 से 48 तक बर्फबारी के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फूल चट्टी से आगे तथा लंबगांव मोटर मार्ग चौरंगी खाल किलोमीटर 23 से 33 तक बर्फवारी के कारण अवरुद्ध है। उधर, उत्तरकाशी जिले के सीमांत विकासखंड मोरी के उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से वहां सेब के बागान मालिकों के चेहरे खिल गए हैं। सेब की फसल के लिए हिमपात का होना आवश्यक है। हिमपात से बगीचों में पर्याप्त नमी आती है जिससे सेब, नाशपाती, आड़ू सहित अन्य नगदी फसलों की पैदावार अच्छी होती है।

कांग्रेस को बंगाल में टीएमसी के साथ सीट-बंटवारे का समझौता होने की उम्मीद: रमेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जंगीपुर (पश्चिम बंगाल)/भाषा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीटें देने में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी की अनिच्छा के बावजूद कांग्रेस ने राज्य में टीएमसी के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीट-बंटवारे की व्यवस्था हासिल करने को लेकर बृहस्पतिवार को आशावादी रुख व्यक्त किया। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का सर्वोपरि उद्देश्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को हटाना है।

रमेश ने कहा, गठबंधन में, देने और लेने की प्रवृत्ति होती है। हम राज्य में संयुक्त रूप से सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए आशान्वित हैं जो इसमें शामिल सभी दलों को संतुष्ट करेगा। ममता बनर्जी ने 'इंडिया' गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और हम इस रुख का स्वागत करते हैं। अल्पसंख्यक बहुल जिले मुर्शिदाबाद में फिलहाल लोकसभा की तीन में से एक सीट कांग्रेस के पास है। रमेश की इस टिप्पणी के पूर्व बनर्जी ने कांग्रेस को कोई भी सीट आवंटित नहीं करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पार्टी ने भाजपा की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ गठबंधन किया है। रमेश ने कहा, मैंने उनके बयान को सुना है, लेकिन यह उनकी राय को दर्शाता है, गठबंधन की सहमति को नहीं। टीएमसी और कांग्रेस दोनों का आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का साझा लक्ष्य है।

अंतरिम बजट शब्दों का मायाजाल, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं: खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट सिर्फ रंग-बिरंगे शब्दों का मायाजाल है तथा इसमें गरीबों और मध्य वर्ग लिए कुछ नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जितने वादे किए गए, उनमें से कितने पूरे हुए। खरगे ने एक बयान में कहा, मैंने बजट भाषण सुना। मैंने सोचा था कि वित्त मंत्री गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नई योजनाएं लाएंगी। उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल की तरह मोदी सरकार का अंतरिम बजट केवल रंग-बिरंगे शब्दों का मायाजाल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इसमें ठोस कुछ नहीं है, बड़े-बड़े और खोखले दावे करना इस सरकार की आदत है। खरगे ने कहा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वे 2014 और 2024 की तुलना करने के लिए श्वेत पत्र सदन में रखेंगी। उनको बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जितने वादे किए गए, उनमें से कितने पूरे हुए? कितने बाक़ी हैं? बजट में उन वादों का कोई ज़िक्र नहीं है। उन्होंने कहा, सालाना दो करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करना, 2022 तक सभी को पक्का घर, 100 स्मार्ट सिटी, ये सभी वादे आज तक पूरे नहीं हुए।

नीतीश ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट की सराहना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट की प्रशंसा की। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह अंतरिम बजट है। जनता दल (यूनाइटेड)- जदयू के अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को सकारात्मक करार देते हुए ''स्वागत योग्य'' बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने तीन नए आर्थिक रेल गलियारे स्थापित करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे 'लॉजिस्टिक दक्षता' बढ़ेगी और देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में मदद भी मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना, मनरेगा बजट को 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए करने और स्टार्टअप के लिए कर लाभ जैसे उपायों की भी सराहना की।

गौरतलब है कि नीतीश कुमार हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुए हैं।

अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों में चयनित युवाओं का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

नई दिल्ली/भाषा। अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों में चयनित युवाओं की भर्ती की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एनआईसीसी) की पूर्व सैनिक इकाई के बैनर तले युवाओं ने बृहस्पतिवार को यहां जंतर-मंतर पर चार दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया। आयोजकों ने कहा कि पहले दिन विरोध प्रदर्शन में 300 से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

एआईसीसी की पूर्व सैनिकों की शाखा के कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने कहा, अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों में चयनित हुए लगभग 1.5 लाख युवा अब भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सेवाओं में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और अंतिम चयन के लिए अर्ह घोषित किए गए थे। हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इन युवाओं को सेना में नियुक्ति के लिए मंजूरी दिए जाने की मांग की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। केंद्र पर निशाना साधते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार इन युवाओं की भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने कहा, 60 लाख से अधिक युवाओं ने शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लिया था और पूरे देश से 1.5 लाख से अधिक युवाओं को भर्ती के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। चौधरी ने आरोप लगाया कि इन युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला था और उन्होंने वादा किया था कि लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ।

भाजपा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह और दो पुलिस निरीक्षकों पर मुकदमा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गोंडा (उप्र)/भाषा। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह उर्फ राजा भैया और दो पुलिस निरीक्षकों समेत 12 नामजद और 5060 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक मकान और गुरुद्वारे पर कब्जे के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले साल सितंबर में मनकापुर कस्बे में एक मकान पर कब्जे का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से गुरबचन कौर ने आरोप लगाया था कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है जिस पर पिछले साल 13 सितंबर को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर उप निरीक्षकों सुधीर सिंह और अरुण कुमार ने अन्य का कब्जा करा दिया है।

कौर ने गोंडा से भाजपा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह, मनकापुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और निरीक्षक अरुण कुमार राय समेत 12 लोगों को नामजद और 5060 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे का आदेश देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को प्रकरण में सभी संबंधित लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया था।

पुलिस की छवि व सद्भाव बिगाड़ने के लिए गोहत्या कराने वाले विहिप नेता समेत चार गिरफ्तार

मुरादाबाद (उप्र)/भाषा। उप्र के मुरादाबाद जिले की छजलैट थाने की पुलिस ने गोहत्या से जुड़े दो हालिया मामलों में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) एवं बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू विश्नोई समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है जिसने पुलिस की छवि प्रभावित करने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से यह घटना की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 16 जनवरी को छजलैट थाने के छत्रपुर में एक गाय के अवशेष फेंक दिए थे। विश्नोई एवं अन्य ने गाय चुरा ली और उसे वन क्षेत्र में मार डाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हेमराज मीणा ने कहा, क्षेत्र में तनाव पैदा करने और छजलेट थाने के प्रभारी निरीक्षक को निशाना बनाने के लिए घटनाओं की योजना बनाई गई और उन्हें अंजाम दिया गया।

रांची में हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे में है साढ़े आठ एकड़ जमीन : प्रवर्तन निदेशालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे व उपयोग में यहां करीब 8.5 एकड़ कुल क्षेत्रफल के एक दर्जन भूखंड हैं और यह धन शोधन रोधी कानून के तहत अपराध से अर्जित आय है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के शीघ्र बाद सोरेन (48) को ईडी ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी ने दिन में उनसे सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता के खिलाफ संघीय एजेंसी ने जो आपराधिक मामला दर्ज किया है वह जून 2023 की ईसीआईआर (प्राथमिकी के समान) से उपजा है। इससे पहले, राज्य सरकार के कर्मचारियों और राजस्व विभाग के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए थे। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एजेंसी ने प्रसाद के परिसरों से 11 बड़े बक्से बरामद किए जिनमें जमीन के दस्तावेज रखे हुए थे। साथ ही, 17 मूल खाते भी बरामद किए थे। ईडी का दावा है कि प्रसाद भूमि रिकॉर्ड और उनके सरकारी स्वामित्व विवरण के कई मूल खातों के संरक्षक थे।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि प्रसाद भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे जिनमें मूल रिकॉर्ड का फर्जीवाड़ा भी शामिल है और वह फर्जी तरीके से कई संपत्ति की खरीद से जुड़ी गतिविधियों में कई व्यक्तियों के साथ संलिप्त थे। ईडी ने झारखंड सरकार के साथ यह सूचना साझा की जिसने रांची के सदर पुलिस थाने में एक जून 2023 को प्रसाद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। केंद्रीय एजेंसी ने 26 जून 2023 को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने के लिए इस प्राथमिकी का संज्ञान लिया।

ईडी का दावा है कि प्रसाद, हेमंत सोरेन की अवैध संपत्तियों सहित कई संपत्तियों की खरीद एवं उन्हें छिपाने में अन्य लोगों के साथ साजिश रचने में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसने कहा कि ये विवरण भी प्रसाद के मोबाइल फोन से हासिल किए गए। आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, सोरेन को बुधवार रात 10 बजे राजभवन से ईडी ने गिरफ्तार किया।

झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की

रांची/भाषा। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से बृहस्पतिवार को मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए उनके दावे को जल्द से जल्द स्वीकार करने का उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस मामले पर निर्णय लेंगे। चंपई सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा, हमने राज्यपाल से जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया क्योंकि झारखंड में 20 घंटे से अधिक समय से कोई सरकार नहीं है।

हेमंत सोरेन को बुधवार रात यहां धनशोधन मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन झामुमो विधायक दल के नेता चुने गए थे। चंपई सोरेन ने 'एक्स' पर कहा, हम एकजुट हैं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है; इसे कोई नहीं तोड़ सकता। झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा जारी एक वीडियो में 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 43 विधायकों का समर्थन दिखाया गया है।

सरफराज खान को रिचर्ड्स, कोहली और मियांदाद की सूची में जगह बनाने की उम्मीद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विशाखापत्तनम/भाषा। घरेलू क्रिकेट में बनाए ढेरों रनों ने सरफराज खान के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का दरवाजा खोल दिया है लेकिन इस बल्लेबाज का मानना है कि सीखना हमेशा जारी रहता है और वह विराट कोहली, विव रिचर्ड्स और जावेद मियांदाद जैसे दिग्गजों की सूची में जगह बनाना चाहते हैं। चोटों के कारण लोकेश राहुल और रविंद्र जडेजा के बाहर होने के बाद सरफराज को इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के लिए हाल में भारतीय टीम में शामिल किया गया।

मुंबई के इस बल्लेबाज ने सीखने की अपनी प्रक्रिया पर बात करते हुए कहा, मुझे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सर विवियन रिचर्ड्स की बल्लेबाजी देखना पसंद है। यहां तक कि जावेद मियांदाद की भी क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि मैं उनकी तरह बल्लेबाजी करता हूं। मैं जो रूट की बल्लेबाजी भी देखता हूं। सरफराज ने 'जियो सिनेमा' से कहा, जो भी सफल हो रहा है, मैं उन्हें खेलते हुए देखता हूं कि वे ऐसा कैसे कर रहे हैं जिससे कि मैं सीख सकूं और इसे लागू कर सकूं। मैं भविष्य में रणजी ट्रॉफी खेलूं या भारत के लिए खेलूं, मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। सरफराज की नजर में उनके जीवन के असली हीरो उनके पिता नौशाद अहमद हैं जिन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने में असंख्य घंटे समर्पित किए।

सरफराज ने कहा, मेरे पिता ने मुझे क्रिकेट से जोड़ा और मैं हमेशा सोचता था कि मैं क्यों खेल रहा हूं। मैं एक आक्रामक बल्लेबाज हूं और मैं दूसरों की तुलना में जल्दी आउट हो जाता था और बड़ी पारियां खेलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, दूसरों को सफल होते देखना निराशाजनक था जबकि मैं रन नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरे पिता हमेशा कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और मेरे पास जो कुछ भी है वह उसी काम का परिणाम है।

कार हादसे के बाद पैर खोने का डर था, कहा पंत ने

नई दिल्ली/भाषा। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा है कि 13 महीने पहले हुए भयावह कार हादसे के बाद उन्हें अपना दाहिना पैर गंवाने का डर था। पंत दिसंबर 2022 में दिल्ली से अपने परिवार के पास अपने शहर रूड़की जा रहे थे जब उनकी कार सड़क के बीच डिवाइडर से टकरा गई। वह उस समय मीरपुर टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाकर बांग्लादेश से लौटे ही थे। उन्होंने स्टार स्पोटर्स की सीरिज 'बिलीव : टू डैथ एंड बैक' में कहा, अगर कोई नस क्षतिग्रस्त होती तो पैर गंवाने का डर था। मैं उस समय डर गया था। पंत ने कहा, मैंने एसयूवी ली थी लेकिन वह बाद में सेडान लग रही थी। हादसे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके दाहिने घुटने की हड्डी खिसक गई थी और उन्हें काफी दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा, वहां आसपास कोई था तो मैंने पूछा कि पैर को वापिस जगह पर लाने में मदद कर सकता है। उसने मेरे घुटने को सही जगह पर पहुंचाने में मदद की। दो व्यक्तियों रजत कुमार और निशु कुमार ने पंत को उनकी एसयूवी से निकाला जो बाद में आग की लपटों में थी। पंत ने कहा, जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ। हादसे के समय चोट के बारे में तो पता था लेकिन मैं खुशकिस्मत था क्योंकि यह और गंभीर हो सकती थी।

विदेशों के बजाय भारत में एटीपी टूर्नामेंट में खेलने पर ध्यान लगाएं भारतीय खिलाड़ी: अमृतराज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। भारत के महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज ने गुरुवार को सुझाव दिया कि देश के खिलाड़ियों को इस समय चैलेंजर्स टूर्नामेंट में खेलने पर ध्यान लगाना चाहिए जिसके लिए उन्हें विदेश की तुलना में घरेलू कोर्ट पर नियमित रूप से खेलना चाहिए।

अमृतराज जब खेलते थे तो उन्होंने ब्योर्न बोर्ग, जॉन मैकेनरो और रॉड लीवर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को हराया था।

उन्होंने अगले हफ्ते यहां होने वाले चेन्नई ओपन चैलेंजर से पहले कहा कि यह टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों के लिए रैंकिंग अंक हासिल करने का अच्छा मौका मुहैया कराता है।

अमृतराज ने कहा, इससे उन्हें एक मौका मिलता है। अगर आपको मौका नहीं मिले तो आप कोशिश भी नहीं कर सकते। आपको कहीं और जाकर अंक हासिल करने के बजाय भारत में खेलने पर ध्यान लगाना चाहिए। खर्चा, प्रतिस्पर्धा और घरेलू कोर्ट, ये सभी चीजें मायने रखती हैं।

उन्होंने कहा, हम भारतीयों के लिए इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, पहले तो हमें एक टूर्नामेंट में खेलना चाहिए और अगर हम चैलेंजर में भी जगह नहीं बना पाते तो ग्रैंडस्लैम के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है।

अमृतराज ने कहा, आप इनमें सुमित नागल और मुकुंद शशिकुमार जैसे खिलाड़ियों से विदेशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करोगे ही। इसलिए स्थानीय टूर्नामेंट इस स्तर पर अहमियत रखते हैं।

सुविचार

यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुःख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

संतुलित बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया अंतरिम बजट संतुलित होने के साथ ही देश के दीर्घकालीन विकास को ऊर्जा देनेवाला है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा। सरकार ने भविष्य के लिए विकास का खाका तैयार किया है, वहीं अतीत में प्राप्त की गईं उपलब्धियों को भी गिनाया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद करना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। वहीं, पीएम-जनधन के तहत बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण होना बताता है कि एक दशक में आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचने से वे कितने सशक्त हुए हैं। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो बहुत बड़ी राशि है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बैंक खाते न खुले होते तो बिचौलियों की 'पौ-बारह' हो जाती। सरकार को इसका श्रेय देना होगा कि जन-जन तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने से भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिली है। इस बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में की गई घोषणा ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इस तरह हर परिवार सालाना 18,000 रुपए तक की बचत करने में सक्षम होगा। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आने वाले एक दशक में भारत ऊर्जा क्षेत्र में जो कीर्तिमान रचेगा, उसकी नींव इस बजट पर टिकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने से (स्वास्थ्य) सेवाओं को बल मिलेगा। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना की शुरुआत का फैसला प्रासंगिक है।

बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसका लाभ महानगरों से लेकर गांव-ढाणियों तक के निवासियों को मिलेगा। रेल के 40,000 सामान्य डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदलने का फैसला यात्री-सुविधाओं की दृष्टि से लाभदायक है। डिब्बों में समयानुसार इसी तरह सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ियों आदि में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना का शुभारंभ करने की घोषणा ने लाखों लोगों को नई उम्मीदें दी हैं। इससे उनके अपने घर का सपना साकार होगा। निर्मला सीतारमण द्वारा की गई इस घोषणा की गूंज मालदीव से लेकर चीन तक सुनाई देगी कि 'घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं से जुड़ीं परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।' जब राज्यों को विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा संबंधित विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, तो निश्चित रूप से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन होगा। 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने के फैसले का लाभ महिलाओं और उनके परिवारों को मिलेगा। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण को ध्यान में रखते हुए तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताया है। इन पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रस्ताव रखना उचित है। 'विकसित भारत' का निर्माण उसी स्थिति में संभव है, जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन हो। इस बजट में आयकरदाताओं को 'बड़ी राहत' मिलने की उम्मीद थी। सरकार को अगले बजट में इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी।

-नरेन्द्र मोदी

पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।

-निर्मला सीतारमन

जम्मू-कश्मीर की जनता परिवारवाद की राजनीति के कारण विकास से अछूती थी। सरकार ने जमीनी स्तर पर विकास पहुँचाने के उद्देश्य से यहाँ पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे अब शासन-व्यवस्था परिवारवाद से मुक्त होकर आम जनता के हाथों में पहुँची है।

-अमित शाह

प्रेरक प्रसंग

वीरांगना का संघर्ष

महारानी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी रानी थीं। इन दोनों का एक पुत्र हुआ 'दलीप सिंह'। वर्ष 1839 में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। पंजाब राज्य में अराजकता का माहौल हो गया। रानी जिंद कौर ने केवल पांच साल की आयु में ही 'दलीप सिंह' को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर काम-काज देखती रहीं। जिंद कौर अपनी कुशल नीतियों से ईस्ट इंडिया कम्पनी के विरुद्ध मोर्चा लेती रहीं। 1848 में अंग्रेजों ने अभियोग चलाकर इन्हें लाहौर से हटा दिया। महारानी के अलावा किसी में इतनी हिम्मत न थी जो अंग्रेजों से मुठभेड़ करता। रानी जिंद कौर को चुनार किले में नज़रबंद कर दिया गया और उनके बेटे को अंग्रेजों ने नौ साल की उम्र में लंदन भेज दिया। मां ने हिम्मत नहीं हारी। वे भेष बदलकर किसी तरह कैद से निकल भागीं और नेपाल जा पहुंची। रानी जिंद कौर ने अपने बेटे दलीप सिंह से मिलने के कई प्रयास किए। लेकिन अंग्रेजों ने एक भी पत्र उनके बेटे के हाथ न लगने दिया। समय बीतता रहा। उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। वर्ष 1861 में इंग्लैंड में वे किसी तरह अपने पुत्र दलीप सिंह से मिल पाईं।

सामयिक

दशकों बाद देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

आर.के. सिन्हा

PTI

भारत ने एक बार फिर से शत्रुओं को साफ संकेत और सख़्त संदेश दे दिया कि वह अपनी सरहदों की निगाहबानी करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करता रहेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतरिम बजट को देश के सामने पेश किया। उन्होंने बजट प्रस्तावों में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वित्त साल की तुलना में 11.1 फीसद अधिक धन की व्यवस्था की। यह राशि देश के जीडीपी के कुल 3.4 फीसद होगी। यह एक स्पष्ट और सख़्त संदेश है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दो घोषित शत्रुओं के साथ भारत कभी भी अपनी सीमाओं की रखवाली करने में कमजोर रहने वाला नहीं है। यह दोनों ही देश घनघोर रूप से धूर्त हैं। इनसे भारत कई बार जंग भी कर चुका है। अगर एक 1962 की जंग को छोड़ दिया जाए तो भारत ने हरेक बार इन्हें करारा जवाब भी दिया है। 1962 की जंग को हुए तो अब छह दशकों का लंबा वक्त हो गया है। उसके बाद चीन ने हमारी सीमाओं के अतिक्रमण करने की जब-जब कोशिश की तो उसे कसकर मार पड़ी। बुद्ध, महावीर और गांधी का भारत अपने पड़ोसियों से सौहार्द पूर्वक संबंध रखना ज़रूर चाहता है। वह अपने पड़ोसियों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी करता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने किसी देश में जाकर कभी भी हमला नहीं किया है। पर भारत भी अब किसी की धौंस में आने वाला नहीं है। इस बीच, रक्षा क्षेत्र को लेकर सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भर बनने का संकल्प ले चुका है। नरेन्द्र मोदी के केन्द्र सरकार पर 2014 में सत्तासीन होने के बाद सरकार की कोशिश रही है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों का उत्पादन खुद करें।

भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप सहित भारतीय उद्योग द्वारा रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार लाए हैं, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। एक सुखद बात यह भी है कि टाटा, लार्सन एड टुब्रो, महिन्द्रा और जिंदल जैसे मशहूर उद्योग समूह रक्षा उत्पादन में निवेश कर रहे हैं। टाटा समूह रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयार कर चुका है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा एडवांस्ड मैटीरियल्स रक्षा उत्पादन के काम में खासतौर पर बहुत एक्टिव हैं। भारत के सालाना लगभग दो लाख करोड़ के रक्षा बाजार में कब्जा करने में टाटा समूह एक बड़े प्लेयर के रूप में उबर रहा है।

भारत को अपने दुश्मनों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए देश को इस क्षेत्र में हर हालत में एक स्तर तक तो आत्म निर्भर होना ही होगा। इस लिहाज से देश के निजी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11 प्रतिशत की कमी आई है, इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार देश बना हुआ है। बीते पांच सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए, उनमें से 11 प्रतिशत अकेले भारत ने खरीदे। सऊदी अरब (9.6 फीसदी) खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं इनके बाद कतर (6.47), ऑस्ट्रेलिया (4.77) और चीन (4.77) का नंबर आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक इसलिए बना क्योंकि वह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का पड़ोसी है। चीन और पाकिस्तान को भारत का विकास कभी भी रास नहीं आता। यह दोनों मुल्क भारत को किसी ना किसी तरह से क्षति पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए भारत के पास अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सोच के चलते ही अपने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को दिल खोल धन दिया। कमजोर को तो दुनिया जीने का भी अधिकार देने के लिए राजी नहीं है।

यह भी गौरतलब है कि भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले नौ साल में देश में रक्षा निर्यात में 23 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल 100 से अधिक कंपनियों के जरिए देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ा सामान का उत्पादनहो रहा है। इन्हें 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत बनाया जा रहा है। देश रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है। विगत वित्त साल भारत ने 16 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जिसमें सैन्य हार्डवेयर यानी गोला-बारूद और हथियार शामिल हैं। यह पिछले साल से करीबन तीन हजार करोड़ रुपए अधिक है और पिछले नौ वर्षों में सबसे अधिक और 2014 से 23 गुणा है।

अब जानेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 क्यों पेश किया? इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019 में अंतरिम बजट पेश किया था। तो, अंतरिम बजट क्या है और इसे 2024 में पूर्ण बजट के बजाय क्यों पेश किया जा रहा है। क्या होता अंतरिम बजट है?दरअसल जिस साल देश में लोकसभा चुनाव होने होते है, उस वर्ष के दौरान मौजूदा सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती है। इसी वजह से वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करते हैं जो अल्प काल के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व की रुपरेखा तय करते हैं। अंतरिम बजट तब तक के लिए होता है जब तक देश में नई सरकार चुनी नहीं जाती। यह तो मानकर चलिए जब देश का पूर्ण बजट पेश होगा तब भी रक्षा क्षेत्र के साथ न्याय ही होगा।

विशेष

164 वर्ष पूर्व पेश हुआ था भारत का पहला बजट

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9034304041

एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट लंबे अपने बजट भाषण के साथ ही संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार का 12वां और मौजूदा कार्यकाल का छठा बजट था। निर्मला सीतारमण पेश किया गया यह बजट अंतरिम बजट था, पूर्ण बजट लोकसभा चुनावों के बाद बनने वाली सरकार द्वारा संभवतः इसी साल जुलाई महीने में पेश किया जाएगा, इसीलिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसी तरह की बड़ी घोषणाएं करने से परहेज किया। बजट निर्माण की पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की ही होती है और यह लगातार छठा ऐसा अवसर था, जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। हालांकि उन्होंने इस दौरान अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण दिया। अब यह भी जान लें कि 'बजट' आखिर होता क्या है? संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाने वाला 'वार्षिक वित्तीय विवरण' केन्द्र सरकार का बजट कहलाता है, जो देश के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर बजट एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित राजस्व और व्यय का अनुमान होता है, जो भविष्य की वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

सरकार बजट के जरिये आर्थिक नीतियों को लागू करती है और हर साल पेश किए जाने वाले बजट का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। इस दस्तावेज में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय पर विस्तृत टिप्पणियां दी जाती हैं। बजट एक ऐसा दस्तावेज है, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। केन्द्रीय बजट को राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जा सकता है। बजट में शामिल प्रस्ताव संसद की स्वीकृति मिल जाने के बाद 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं, जो अगले साल 31 मार्च तक लागू रहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव होने की स्थिति में पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने के बजाय अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है और पूर्ण बजट चुनाव के बाद ही प्रस्तुत होता है। भारत में वित्त वर्ष प्रतिवर्ष एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और बजट के विवरण में इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा शामिल होता है। सरल शब्दों में कहें तो बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है, जिसके जरिये यह तय करने का प्रयास किया जाता है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्च को किस हद तक बढ़ा सकती है। यह कवायद इसीलिए होती है क्योंकि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है।

बजट आमतौर पर तीन प्रकार का होता है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट में आय और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है जबकि अधिशेष बजट में सरकार की आय खर्चों से अधिक होती है और घाटे के बजट में सरकार के खर्च उसकी आय के स्रोतों से अधिक होते हैं। सरकारी बजट तीन प्रकार के होते हैं, परिचालन या चालू बजट, पूंजी या निवेश बजट और नकदी या नकदी प्रवाह बजट। सरकार की आय के प्रमुख साधनों में विभिन्न प्रकार के कर और राजस्व, सरकारी शुल्क, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि तरीके शामिल होते हैं। बजट की पहले कुछ प्रतियां ही छपती थी लेकिन अब बजट पूरी तरह डिजिटल हो गया है। 2016 तक फरवरी माह के अंतिम दिन आम बजट पेश किया जाता था किन्तु 2017 में तत्कालीन वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्यदिवस पर शाम पांच बजे पेश किया जाता था लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। 2017 से पहले रेल बजट भी अलग से पेश किया जाता था लेकिन 2017 में उसे आम बजट में ही समाहित कर दिया गया। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था लेकिन उसके बाद इसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश करना शुरू कर दिया गया। 1950 तक बजट का मुद्रण राष्ट्रपति भवन में होता था किन्तु इसके लीक होने के बाद इसका मुद्रण दिल्ली की मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगा और 1980 से वित्त मंत्रालय के अंदर सरकारी प्रेस में ही इसका मुद्रण होता है। 1947 से लेकर अब तक देश में 73 आम बजट, 14 अंतरिम बजट व 4 विशेष या मिनी बजट पेश किए जा चुके हैं। वैसे भारत में बजट पेश करने का सिलसिला 164 वर्ष पहले शुरू हुआ था जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्तमंत्री आर के षणमुगम चेट्टि ने 26 नवम्बर 1947 को पेश किया था, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाते हुए केवल अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी।

बजट को लेकर दिलचस्प तथ्य यह भी है कि देश के इतिहास में तीन ऐसे अवसर भी आए हैं, जब वित्तमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री ने आम बजट पेश किया। सबसे ज्यादा देर तक बजट भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। 1977 में मात्र 800 शब्दों का सबसे छोटा भाषण वित्तमंत्री हीरुभाई मुलजीभाई पटेल ने जबकि शब्दों के लिहाज से कुल 18650 शब्दों का सबसे बड़ा बजट भाषण 1991 में मनमोहन सिंह ने दिया था। उसके बाद 2018 में अरुण जेटली ने 18604 शब्दों का बजट भाषण दिया था। बतौर वित्तमंत्री सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1962-69 के बीच 10 बार बजट पेश किया था। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संयुक्त मोर्चा सरकार में 1996 से 1998 तक और फिर यूपीए-1 तथा यूपीए-2 सरकार में कुल 9 बार, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने इंदिरा सरकार में 1982 से 1984 तक और मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 2012 तक कुल 8 बार बजट पेश किया। यशवंत राव चव्हाण, सीडी देशमुख तथा यशवंत सिन्हा ने 7-7 बार जबकि मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णमाचारी ने 6-6 बार बजट पेश किया। इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्तमंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया था।

नजरिया

विकसित भारत के द्वार खोलेगा यह बजट

सुरेश हिंदुस्तानी

केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट में हालांकि कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार पिछले बजट के कारण भारत की दशा और दिशा सुधरी हुई दिखाई देती है, वैसी ही राह का अनुसरण इस बार के बजट में किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले बजटों के माध्यम से भारत ने अर्थ व्यवस्था के मामले में नए कीर्तिमान बनाते हुए एक वैश्विक आयाम स्थापित किया है। जिसकी चर्चा पूरे देश में तो है ही, साथ विश्व के अनेक देश भारत के इन आर्थिक कदमों की प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां एक ओर विश्व के अनेक बड़े देशों की अर्थ व्यवस्था धराशायी हो गई थी, वहीं भारत ने सीना चौड़ा करके एक ऐसी राह का निर्धारण किया, जो भारत को विकसित बनाने में समर्थ है। इस बार का बजट भी निश्चित ही भारत को गरीबी से उबारने का सामर्थ्य पैदा करने वाला ही कहा जाएगा, क्योंकि इस बजट में केंद्र सरकार ने उन बातों पर पुनः फोकस किया जो भारत की गरीब जनता के लिए प्रगति का द्वार खोलती हैं।

केंद्र सरकार भारत की जनता को जातियों के आधार पर नहीं देखती। उसकी नजर में देश में केवल चार ही जातियां हैं। जिसमें किसान, युवा, महिला एवं गरीब ही आते हैं। यह किसी भी जाति का क्यों न हो इसके लिए इस बजट में भी ध्यान रखा गया है। वास्तव में जिस देश में यह चार वर्ग सशक्त हो जाएं तो उस देश को प्रगति की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने विकास के रास्ते पर दौड़ लगाई है। इस देश में अब तक करोड़ों वास्तविक गरीबों को आवास मिला है।

इसके पूर्व सरकारी सुविधा से निर्मित आवासों में बंदरबांट होता रहा है। जिसमें कई आवास नेताओं के परिजनों को ही मिल जाते थे, जो एक बड़े घोटाले का रूप ले चुका था। केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें पारदर्शी तरीके से कार्य करते हुए उन्हीं गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, जिनको वास्तव में जरूरत थी। यह आवास हर वर्ग को उपलब्ध कराए, फिर चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान। सरकार भारत की समस्त जनता को अपना परिवार मानकर कार्य कर रही है। उसका नारा भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि आगामी समय में देश के गरीब समाज को गरीबी से बाहर निकालने के लिए दो करोड़ आवास निर्मित किए जाएंगे। इससे जिन मजदूरों की आय का बड़ा हिस्सा मकान किराए के रूप में व्यय होता था, उससे बचा जा सकेगा। मोदी सरकार का यह कदम मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला ही कहा जाएगा। इसलिए इस बजट को मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर इस बजट को गरीबों को सशक्त बनाने वाला बजट निरूपित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने इस बजट में व्यापारी वर्ग का भी खास ध्यान रखा है। सरकार ने आयकर को यथावत रखा है। इसी प्रकार महिलाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है। सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बजट के माध्यम से तीन करोड़ और महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। विकास की आधारशिला का मुख्य सूत्र माने जाने वाले अधोसंरचना पर भी मोदी सरकार ने प्रमुखता से ध्यान दिया है। इसके विकास के लिए बजट में बढ़ोत्तरी की है। कहा जाता है जिस देश की अधोसंरचना मजबूत होती है, वह देश विकास की राह पर तेज गति से भागता है। क्योंकि इससे समय की बचत होती है और काम भी आसान हो जाता है। यातायात को सुगम बनाने की दिशा में यह बजट बहुत ही प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है, तब से अधोसंरचना को विकसित करने के तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं। जो काम वर्षों में होता था, वह काम इस सरकार के कार्यकाल में महीनों में उच्च गुणवत्ता के हो रहे हैं। इन कामों में पारदर्शिता लाई गई है। इसी प्रकार रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भी व्यापक रूपरेखा भी इस बजट में दिखाई देती है। 40 हजार सामान्य श्रेणी के कोचों को वंदे भारत की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जिससे भारत की गरीब जनता की रेल यात्रा आरामदायक हो सके। इसी प्रकार अधूरे पड़ी रेल परियोजना को भी बहुत जल्द पूरा करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही तीन नई परियोजना को भी प्रस्तावित किया गया है। इससे यह बजट बहुत ही संतुलित बजट माना जा रहा है।

मोदी सरकार का यह बजट आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐसा कदम माना जा रहा है। जो भारत की मजबूती के लिए नई तस्वीर निर्मित करेगा। आज भारत की जो मजबूत छवि विश्व के देशों में दिखाई दे रही है, वह वर्तमान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण ही संभव हो सका है। भारत फिर से उसी राह पर उसी राह पर मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए कहा सकता है। यही कदम भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन करने वाला होगा।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

श्रीलंका का विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक कानून बना

कोलंबो/दक्षिण भारत। श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए बृहस्पतिवार को एक विवादास्पद विधेयक का अनुमोदन किया, वहीं विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करेगा। संसद के संचार कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि स्पीकर महिंदा यापा अबेयवर्धने ने हस्ताक्षर कर विधेयक को प्रमाणित किया। अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर, इस विधेयक को प्रमाणित न करने की मांग के बावजूद स्पीकर ने इस पर हस्ताक्षर किया। संसद ने पिछले सप्ताह संशोधनों के साथ इस विधेयक को मंजूरी दी थी। नए कानून से ऑनलाइन सुरक्षा आयोग की स्थापना होगी जिसे अपराधों पर दंडात्मक निर्णय लेने की शक्तियां दी गई हैं। ऑनलाइन मंचों पर झूठे बयान देने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम पांच साल की कैद या अधिकतम पांच लाख श्रीलंकाई रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मुर्मू ने 'उद्यान उत्सव 2024' का उद्घाटन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को अमृत उद्यान में 'उद्यान उत्सव 2024' का उद्घाटन किया जिसे शुक्रवार से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी। पंद्रह एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी और एक 'सेल्फी पॉइंट' भी होगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (1 फरवरी, 2024) उद्यान उत्सव-1- 2024 की शोभा बढ़ाई। इसमें कहा गया कि उद्यान उत्सव-1 के तहत अमृत उद्यान दो फरवरी से 31 मार्च, 2024 तक (सोमवार को छोड़कर जो रखरखाव का दिन है) जनता के लिए खुला रहेगा। पहली बार, अमृत उद्यान में आने वाले आगंतुकों के लिए 18 किस्मों के 42,000 ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन विकसित किया गया है। इसके साथ ही 225 साल पुराना शीशम का पेड़ और बोनसाई उद्यान (300 से अधिक बोनसाई, जिनमें से कई दशकों पुराने हैं) आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से हैं। बयान में कहा गया, बुकिंग ऑनलाइन और साथ ही गेट नंबर 35 के बाहर स्थित स्वयं-सेवा कियोस्क के माध्यम से की जा सकती है।

प्रदर्शन

असम आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) ने गुरुवार को गुवाहाटी में बाल एवं महिला कल्याण निदेशालय पर अपने अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए।

शिमला में लंबे इंतजार के बाद हुई मौसम की पहली बर्फबारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों और जनजातीय इलाकों में बृहस्पतिवार को मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रही जबकि राज्य की राजधानी शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से निवासियों, पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला बृहस्पतिवार को बर्फ की पतली चादर में लिपटा दिखा जबकि कुफरी और फागु के बीच पांच किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढंक गया। ठंड के बावजूद पर्यटक और निवासी बर्फ का आनंद लेने के लिए शहर के मध्य में स्थित माल रोड और रिज पर इकट्ठा हुए। शिमला में बुधवार रात को भारी ओलावृष्टि हुई और उसके बाद रुक-रुक कर बारिश हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, राज्य में छह राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 240 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं और भारी बर्फबारी एवं बारिश के कारण 677 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं।

केंद्र ने कहा कि किन्नौर और लाहौल एवं

स्पीति के आदिवासी जिलों में 165 सड़कें अवरुद्ध हैं। कुफरी, फागु और नारकंडा में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध होने से ढली से आगे शिमला के ऊपरी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही रुक गई है। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बृहस्पतिवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि बर्फबारी और सड़क पर फिसलन की स्थिति के कारण ढली में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जल्द ही यातायात बहाल हो जाएगा।

राज्य के 12 में से पांच जिलों में मंगलवार रात से रुक-रुक कर बर्फबारी जारी है और स्थानीय मौसम कार्यालय ने एक फरवरी को पांच जिलों शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति में अलग-अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी और बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। वहीं, तीन और चार फरवरी को आंधी तथा बिजली गिरने के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान से किसानों और फल एवं सब्जी उत्पादकों को राहत मिली है जिन्हें लंबे समय तक सूखे के कारण फसल का भारी नुकसान हुआ था। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बारिश का मौसम रबी फसलों के लिए फायदेमंद होने की संभावना है। शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एम. के. सेठ ने कहा, भारी बर्फबारी ने पर्यटन और इससे जुड़े उद्योग को खुश कर दिया है और हम फरवरी में अच्छे पर्यटन की उम्मीद कर रहे हैं। शिमला में सप्ताहांत के दौरान बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। शिमला जिले के चिड़गांव में 75 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी जबकि शिकारी माता में 60 सेमी, कोठी में 50, चांशेल तथा कामरू नाग में 45, मनाली में 37, केलांग में 32, बड़ा बंगाल तथा पराशर झील में 30, तिंदी, पांगी, जोत तथा नौराधार में 25-25, कुकुमसेरी में 18.4, कोकसर में 16.2 और सांगला में 12.2 सेमी बर्फ पड़ी।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 11 दिनों में करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने नये मंदिर में भगवान श्रीराम का दर्शन-पूजन किया और 11 करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह जानकारी दी गयी। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पिछले 11 दिनों में दान पेटियों में करीब आठ करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जबकि चेक और ऑनलाइन के जरिए करीब 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। उन्होंने बताया कि भव्य मंदिर के गर्भगृह के सामने चार बड़े आकार की दान पेटियां रखी गई हैं, जिनमें श्रद्धालु राशि जमा कर रहे हैं ।

इसके अलावा 10 कम्प्यूटरीकृत काउंटरों पर भी लोग दान राशि जमा करते हैं। उन्होंने बताया कि दान काउंटर पर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी नियुक्त हैं, जो शाम को काउंटर बंद होने के बाद प्राप्त दान राशि का हिसाब ट्रस्ट कार्यालय में जमा करते हैं। गुप्ता ने बताया कि चार दान बक्सों में आए चढ़ावे की गिनती 14 लोगों की एक टीम करती है। उन्होंने कहा कि दानराशि जमा करने से लेकर उसकी गिनती तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है।

अंतरिम बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है: शत्रुघ्न सिन्हा

नयी दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट में युवाओं या गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सदस्य सिन्हा ने कहा, यह अंतरिम बजट इस सरकार का आखिरी बजट है। इसमें ढेर सारी बातें कही गयी हैं। उन्होंने ऐसी योजनाएं घोषित की हैं जो 2047 , 2050 में पूरी होंगी... ये योजनाएं तो रहेंगी लेकिन इनका क्रियान्वयन नयी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, फिर भी लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे सरकार मुख्य मुद्दों-- बेरोजगारी, गरीब, युवाओं और किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, वे घोषणा करते रहे कि हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं लेकिन लोग देख सकते हैं कि यहां प्रति व्यक्ति आय कई अन्य देशों से भी कम है।

इस वर्ष नेटफ्लिक्स पर आएगी 'हीरामंडी : द डायमंड बाजार'

मुंबई/भाषा

संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' इस वर्ष नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित होगी। ओटीटी मंच ने बृहस्पतिवार को बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज का पहला 'लुक' साझा किया। वेब सीरीज का निर्माण भंसाली प्रोडक्शंस ने किया जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शर्मिन सहगल और संजीदा शेख जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। नेटफ्लिक्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' प्रेम, ताकत, बदला और स्वतंत्रता पर आधारित गाथा है। वेब सीरीज के सारांश के अनुसार, 'हीरामंडी में सत्ता को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच एक युवा उत्तराधिकारी सत्ता के बजाय प्यार को चुनता है। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में गति पकड़ रहे आजादी आंदोलन के दौरान की इस कहानी में अंतिम कड़ी तवायफों से संबंधित है।' मोइन बेग की संकल्पना पर आधारित इस सीरीज का निर्माण और निर्देशन भंसाली द्वारा किया गया है। वह प्रेरणा सिंह के साथ इसके निर्माता हैं।

'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' भंसाली की 14 साल की महत्वपूर्ण परियोजना है। उनके द्वारा आखिरी निर्देशित फिल्म आलिया भट्ट अभिनीत 'गंगूबाई काठियावाड़ी' थी जिसने पिछले वर्ष पांच राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। भंसाली ने हाल ही में भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल अभिनीत अपनी अगली फीचर फिल्म 'लव एंड वॉर' की घोषणा की।

'फाइटर' में ऋतिक रौशन के साथ काम कर खुश हैं महेश शेट्टी

मुंबई/वार्ता

अभिनेता महेश शेट्टी फिल्म फाइटर में ऋतिक रौशन के साथ काम कर बेहद खुश हैं। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित एक्शन थ्रिलर 'फाइटर' महेश ने स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नीनाथन की भूमिका निभाई है।

फिल्म फाइटर में ऋतिक रौशन के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर, महेश ने कहा, वायु सेना के शब्दकोष में, एक विंगमैन एक पायलट होता है जो पारस्परिक सहायता प्रदान करते हुए एक उड़ान संरचना के नेता के साथ उड़ान भरता है, इसलिए उनकी बॉन्डिंग हमेशा दूसरे स्तर पर होती है। शूटिंग शुरू होने से पहले ही ऋतिक और मेरे बीच अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो गई थी। जिस तरह से उन्होंने सेट पर यारा के रूप में मेरा स्वागत

किया वह बहुत स्थायी था और पूरी टीम एक बड़े परिवार की तरह थी। वह बेहद सच्चे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है एक ग्रीक भगवान की तरह दिखते हैं लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भी, वह आश्चर्यजनक रूप से मधुर हैं और उनमें मजाकिया स्वभाव है। जिस तरह से उन्होंने हमें कहानियां सुनाईं, उसने हमें हमेशा चकित कर दिया और हम और अधिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। हममें से एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम काम कर रहे थे। वह एक कारण से रितिक रोशन हैं और इसका कारण केवल समर्पण और कड़ी मेहनत है।'

अंजना सिंह की फिल्म 'बड़की दीदी' का टेलीविजन प्रीमियर

मुंबई/वार्ता

बी4यू मोशन पिक्चर्स प्रस्तुत निलाभ तिवारी क्रियेशन्स के बैनर तले बनी फिल्म बड़की दीदी का टेलीविजन प्रीमियर 3 फरवरी को होगा। बड़की दीदी में अंजना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। बी4यू टीम के मारुदा शर्मा ,नेहा उपाध्याय और विशाल यादव ने बताया कि फिल्म बड़की दीदी का टेलीविजन प्रीमियर 03 फरवरी को संध्या 5:30 बजे से टीवी चैनल बी4यू पर होगा। इस फिल्म को भोजपुरी के दर्शन अपने परिवार के साथ मिलकर अगले दिन रविवार 04 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से देख पाएंगे। यह फिल्म आपके वीकेंड को एक शानदार मनोरंजन देने वाला है।

वहीं, इस फिल्म के निर्माता संदीप सिंह, अंजनी तिवारी और निलाभ तिवारी ने कहा कि फिल्म बड़की दीदी की कहानी भोजपुरी समाज की ज्वलंत विषय पर आधारित है।

हमने इसका निर्माण बड़े पैमाने पर भव्यता के साथ किया था, जो अब दर्शकों को टीवी के माध्यम से दिखाई जा रहा है। हम तमाम भोजपुरी के दशकों से आग्रह करेंगे कि आप सभी इस फिल्म को देखें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, ताकि हम आगे भी ऐसी ही अच्छी फिल्में लेकर आपके पास आने को प्रेरित होते रहे। उन्होंने कहा कि इसकी कहानी गीत संगीत और संवाद बेहद सुग्रह्यिय है। इसलिए इस फिल्म को आप सभी एक बार जरूर देखें।

फिल्म बड़की दीदी के निर्देशक संजीव बोहरपी हैं। छायांकन विजय मंडल हैं। नृत्य कानू मुखर्जी का है। मारधाड़ श्रवण कुमार का है। कथा-पटकथा-संवाद -अरबिंद तिवारी का है।

कॉन्सेप्ट संदीप सिंह और कला अंजनी तिवारी का है। संगीत ओम झा का है। गीत प्यारेलाल यादव,अरबिंद तिवारी, धरम हिंदुस्तानी, राकेश निराला ने दिया है।फिल्म में अंजना सिंह के साथ शिवम तिवारी,नीलू शंकर सिंह, समीरा शेख, विनोद मिश्रा, निशा तिवारी , रूपा सिंह, गोपाल चौहान, सत्यप्रकाश सिंह, वंदना दुबे,प्रेम दुबे,सतेंद्र सिंह, संजीव बोहरपी,आशुतोष राय,कविता राज, सुनीता राय , अंजली त्रिपाठी संजीव मिश्रा,अंशु तिवारी,मुख्य भूमिका में हैं।

देव आनंद की फिल्मों की पुरानी यादगार चीजों की ऑनलाइन होगी नीलामी

मुंबई/एजेन्सी

महान अभिनेता दिवंगत देव आनंद की फिल्मों की दुर्लभ और पुरानी यादगार वस्तुओं की ऑनलाइन नीलामी होने वाली है। यादगार वस्तुओं में 'बाजी', 'काला बाजार', 'सीआईडी', 'काला पानी', 'गाइड', 'तेरे घर के सामने', 'हरे रामा हरे कृष्णा', 'जॉनी मेरा नाम'' और 'हीरा पन्ना' जैसी क्लासिक फिल्मों की पब्लिसिटी आर्ट शामिल हैं। इसमें 'आराम', 'मिलाप', 'माया', 'मंज़िल', 'कहीं और चल', 'बारिश', 'बात एक रात की', 'सरहद' और 'किनारे किनारे' जैसी उनकी कम प्रसिद्ध फिल्मों के दुर्लभ और पुराने फोटोग्राफिक चित्र, पोस्टर, शोकार्ड, लॉबी कार्ड, गीत पुस्तिकाएं भी शामिल हैं।

मुख्य आकर्षणों में 'काला बाजार' और 'जॉनी मेरा नाम' लॉबी कार्ड का एक दुर्लभ सेट, 'गाइड' से 8 पहली रिलीज प्रचार ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक तस्वीरें, 'हरे राम हरे कृष्णा' से 15 रंगीन फोटोग्राफिक तस्वीरें, दुर्लभ और खूबसूरती से डिजाइन किए गए पोस्टर शामिल हैं। वहीं, 'मुनीम जी', 'मिलाप', 'सरहद', 'माया', 'मंज़िल', 'किनारे किनारे','गाइड', 'जुआरी', 'डार्लिंग डार्लिंग', 'काला पानी' और 'अमीर ग़रीब' के अनूठे भारतीय कोलाज हस्तनिर्मित शोकार्ड शामिल हैं। डेरिवाज और इव्स फिल्म विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता एसएमएम औसाजा ने कहा कि 'बाजी' से छोटी प्रसिद्ध काले और सफेद चांदी की जिलेटिन तस्वीर, 'गाइड' के अंतरराष्ट्रीय लॉन्च के लिए बनाए गए फोटोग्राफिक प्रचार चित्र, सरहद के लिए प्रचार और गीत पुस्तिकाएं, 'काला बाजार' लॉबी कार्ड का पूरा सेट कुछ असाधारण दुर्लभ वस्तुएं हैं, जो इस नीलामी में शामिल होगी। ऑनलाइन नीलामी 8 फरवरी को डेरिवाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी और 10 फरवरी, 2024 को बंद होगी।

फिल्म 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई/वार्ता

सनोज मिश्रा निर्देशित फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। फ़िल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति और वहां पर हो रहे अत्याचारों को इंगित करते हुए बनाई गई है । फ़िल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस कदर वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन के नाम पर हिन्दू महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती किया है और उनकी बात नहीं मानने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया है। वसीम रिजवी फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्माता वसीम रिजवी उर्फ़ जितेंद्र नारायण सिंह हैं। फिल्म के लेखक और निर्देशक सनोज मिश्र हैं। फिल्म के कलाकारों में अर्शिन मेहता , यजुर मारवाह, दीपक कंबोज ,अल्फिया शेख, गरिमा कपूर रीना भट्टाचार्य, गौरी शंकर, देव फौजदार, अनिल अंजुनिल, संजू सोलंकी, डा रामेंद्र चक्रवर्ती, दीपक सूठा, जितेंद्र नारायण सिंह, जनार्दन सिंह मयूर, अनुज दीक्षित, नीत महल शामिल हैं । फिल्म के सह निर्माता क्षत्रपाल सूर्यवंशी, संजय कुमार, और अर्जुन सिंह हैं। फ़िल्म के छायाकार सत्यपाल सिंह, संपादक रंजीत प्रसाद और संगीतकार ए आर दत्ता और हैं।

RNI No. 58061/93. Regn No.:
RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

बसवनगुड़ी के जिनकुशलसूरि जैन दादावाड़ी ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री मणिप्रभ स्वास्थ्य योजना श्रृंखला का छठा नि:शुल्क फर्टिलिटी जाँच, परामर्श एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है।

लोकसभा चुनाव का नतीजा तय नहीं, 'पिक्चर अभी बाकी है': थरूर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पहले से तय होने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दावे को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि पिक्चर अभी बाकी है तथा अंतरिम बजट मोदी सरकार का 'अंतिम बजट' लगता है। थरूर ने जीडीपी को 'गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस' बताने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना भी की और कहा कि इस व्यवस्था के तहत 'जी' का मतलब 'गवर्नमेंटल इंट्रूजन एंड टैक्स टेररिज्म' (सरकारी घुसपैठ और कर आतंकवाद), 'डी' का मतलब 'डेमोग्रेफिक बिट्रेयल' (जनसांख्यिकीय विश्वासघात) और 'पी' का मतलब 'पावर्टी एंड राइजिंग इनिक्वालिटी' (गरीबी और बढ़ती असमानता) है। थरूर ने पीटीआई मुख्यालय में 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में अंतरिम केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि बेरोजगारी की बात वित्त मंत्री के भाषण से पूरी तरह गायब थी। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी के जीवन में सुधार के मामले में सरकार को 'एफ ग्रेड' (अनुत्तीर्ण) मिलता है।

थरूर ने कहा, मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि इतनी चौंकाने वाली है कि नीचे की 20 प्रतिशत आबादी बाजार में उन्हें खरीदने में असमर्थ है, जबकि वे एक या दो साल पहले खरीद सकते थे। यह आम भारतीय के जीवन की वास्तविकता है, यही कारण है कि सरकार चाहती है कि लोग राम मंदिर के लिए गर्व करते हुए वोट करें या बालाकोट, पुलवामा की घटना को लेकर पाकिस्तान पर कथित प्रहार के लिए गर्व के आधार पर वोट दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना था कि भाजपा को 2019 में इसी तरह सफलता मिली थी।

उन्होंने कहा, इस बार राम मंदिर मुद्दा बनने जा रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अबू धाबी मंदिर को जोड़ा जाएगा। स्पष्ट रूप से सरकारें ऐसा करने के लिए नहीं चुनी जाती हैं, सरकारें आम लोगों के जीवन में सुधार के लिए चुनी जाती हैं। क्या इस सरकार ने ऐसा किया? मैं कहूंगा कि उस विशेष मानदंड पर वह (सरकार) पूरी तरह विफल है। यह पूछे जाने पर कि सीतारमण का कहना है कि जुलाई में सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी और भाजपा का दावा है कि 2024 के चुनावों का परिणाम पहले से तय है, थरूर ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा कि मतदान से पहले मतों की गिनती नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के पास अभी भी समय है कि वह मिलकर काम करे और लोगों के समक्ष आर्थिक वास्तविकताओं को रखे। थरूर का कहना था कि यह अंतरिम बजट मोदी सरकार का 'अंतिम बजट' लगता है।

यह बजट 2047 तक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाला : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 01 फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट की सराहना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह 2047 तक पूर्ण विकसित और आर्थिक रूप से मजबूत भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का खाका तैयार किया गया है।

शाह ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों पर रोशनी डालता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लगातार छठी बार संसद में बजट प्रस्तुत किया।

शाह ने 'एक्स' पर 'विकसित भारत बजट' हैशटैग के साथ लिखा, केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट भाषण भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की मोदी सरकार की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों पर रोशनी डालता है। उन्होंने कहा, इन कार्यों की बुनियाद पर विकसित भारत की भव्य इमारत खड़ी की जा रही है। इस उत्कृष्ट यात्रा के माध्यम से देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गहरी सोच वाले बजट भाषण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरिम बजट 'आत्मविश्वास से लबरेज, मजबूत और आत्मनिर्भर विकसित भारत' की दृष्टि को रेखांकित करता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2027 तक बढ़कर 5,000 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा।

सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि इस बजट में 'समाज के हर वर्ग' के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, यह अंतरिम बजट है, लेकिन यह बहुत उत्साहवर्धक है और आगे के रास्ते के लिए भी उम्मीद जगाता है। और इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है... मुझे विश्वास है कि इस बजट से हमें जो भी संकेत मिले हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार...जो अभी शीर्ष पांच में है... 2027 तक पांच हजार अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। (वर्ष) 2030 तक यह बढ़कर 7,000 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व में सरकार ने गरीबों और ग्रामीण भारत के कल्याण के लिए विकास के मायने को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत करीब तीन करोड़ मकान बनने का जिक्र किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, 'न्यू इंडिया' के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी योजना के तहत निर्मित घरों के 70 प्रतिशत स्वामित्व अधिकार महिलाओं के हैं।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु में गुरुवार को वुमेन्स पीस लीग विद्या संस्थान के 70 वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत एवं समारोह अध्यक्ष शीला राव ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कुछ दिनों पूर्व आयोजित विभिन्न क्रीडा स्पर्धाओं के विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर गोपाल एवं वेंकटेश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों को सम्मानित किया।

मानव सेवा के तहत स्कूल के बच्चों को भोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां हनुमंतनगर के तेरापंथ युवक परिषद एचबीएसटी हनुमंतनगर द्वारा मानव सेवा के अन्तर्गत अमृता शिशु निवास बसवनगुडी के लगभग 60 बच्चों की भोजन व्यवस्था परिषद द्वारा की गयी। बच्चों ने उत्सुकता से अपना परिचय दिया। परिषद के अध्यक्ष अंकुश बैद ने आज के मानव सेवा के सहयोगी परिवार प्रेमचंद, नितिन, मनीष हिरावत रतननगर, बेंगलूरु का जैन पट्ट से सम्मान किया। इस सेवा कार्य में सह मंत्री देवेंद्र आँचलिया, सह मंत्री द्वितीय सुमित चिंडालिया की उपस्थिति रही।

जीवन में अधर्म का त्याग करें : आचार्य महेन्द्रसागर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हासन। यहां श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर संघ में आचार्यश्री महेन्द्रसागरजी म. सा. ने अपने प्रवचन में कहा कि अभी तक हमारा संसार से निस्तार नहीं हआ है। उसका कारण यह नहीं कि हमने धर्म नहीं किया इसका कारण है कि हमने अधर्म का त्याग नहीं किया।

धर्म कई बार कई जन्म में किया पर भव निस्तार इसलिए नहीं हुआ कि हमने धर्म बहुत कम किया था या फिर किया नहीं परंतु निस्तार इसलिए नहीं हुआ कि हमने अधर्म का त्याग नहीं किया।

उन्होंने कहा कि संसार मे दो प्रकार के जीव है एक वो जिनको पाप करने पड़ रहे और दूसरे वो जिनको पाप करना पसंद है, अब आप खुद ही सोचिए कि आपकी गिनती किन में होती है। आपको किस श्रेणी में रहना पसंद है।

मणिप्रभ स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बसवनगुड़ी के जिनकुशलसूरि जैन दादावाड़ी ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री मणिप्रभ स्वास्थ्य योजना श्रृंखला का छठा नि:शुल्क फर्टिलिटी जाँच, परामर्श एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। अखिल भारतीय खरतरगच्छ युवा परिषद् व महिला परिषद् बसवनगुड़ी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शिविर में सागर चंद्रम्मा हॉस्पिटल्स का विशेष सहयोग रहा।

संयोजक टीम ने बताया नि:संतान दंपतियों के लिए बेंगलूरु के बेहतरीन फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ आयोजित इस प्रजनन शिविर में आने वाले लोगों को नि:शुल्क परामर्श सत्र के साथ साथ नि:शुल्क फॉलिकल स्कैन और नि:शुल्क वीर्य विश्लेषण का भी लाभ मिला। डॉ. लता ने बताया की चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति ने नि:संतान दम्पत्तियों को भी आशा देना संभव बना दिया है।

फर्टिलिटी विशेषज्ञों की टीम ने नि:संतान दंपत्तियों को उनके आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया है। मणिप्रभ स्वास्थ्य योजना श्रृंखला का सातवाँ शिविर 11 और 25 फ़रवरी को होने जा रहा है। नवजात से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष आयोजित बाल चिकित्सा की सभी समस्याओं का सफल उपचार हेतु नामांकन शुरू है।

अंतरिम बजट कृषि, डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने का 'रोडमैप' : उद्योग जगत

मुंबई/भाषा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र दिग्गजों ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को शोध एवं विकास, प्रौद्योगिकी और भंडारण में निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि, कृषि रसायन, डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एक आशाजनक 'रोडमैप' बताया है। उनका कहना है कि यह पहल किसानों और उनकी आजीविका को सशक्त बनाएगी।

गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम सिंह यादव ने कहा, अंतरिम बजट 2024-25 'अन्नदाता' और हमारे देश की रीढ़ - हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। पीएम-किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से लेकर किसान-केंद्रित नीतियों का विस्तार और नवाचारों को बढ़ावा देने तक, बजट कृषि क्षेत्र में समावेशी, सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया।

पराग मिल्क फूड्स के अध्यक्ष देवेंद्र शाह ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुरपका और मुंहपका की बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ-साथ डेयरी किसानों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा, सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने और डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता बढ़ी हुई उत्पादकता और टिकाऊ विकास की नींव रखती है।

दर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के अत्तीबेले स्थित पार्श्व सुशील धाम में विराजित अवंति पार्श्वनाथ तीर्थ जीर्णोद्धारक आचार्यश्री जिनमणिप्रभ सूरीश्वरजी म. सा., साध्वीश्री प्रीतिसुधाश्रीजी म. सा. का अखिल भारतीय खरतरगच्छ महिला परिषद की सदस्यों ने दर्शन, वंदन एवं व्यावच्च का लाभ लिया। यह जानकारी परमेश्वरी संखलेचना ने दी।

अगले सप्ताह आ सकता है 2014 से पहले के आर्थिक 'कुप्रबंधन' पर श्वेत पत्र

नई दिल्ली/भाषा। सरकार वर्ष 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के 'कुप्रबंधन' के बारे में एक श्वेत पत्र लेकर आने की तैयारी में है। इसे अगले सप्ताह संसद में रखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में पहली बार सरकार 2014 में ही बनी थी। उसके पहले लगातार 10 वर्षों यानी 2004-14 तक मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार रही थी। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी अब जल्द खत्म होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए इस कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने की जानकारी दी।

बजट में महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख नहीं : चिदंबरम

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर 'अमीरों की, अमीरों द्वारा और अमीरों के लिए सरकार होने' का आरोप लगाया और कहा कि अंतरिम बजट में बेरोजगारी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठगंधन (संप्रग) की सरकार में औसत विकास दर 7.5 फीसदी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में औसत विकास दर 6 फीसदी से भी कम रही है। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, पिछले 5-10 वर्षों में भारत कैसे आगे बढ़ा है, विगत तीन दिनों के दौरान इस बारे में सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए। माननीय राष्ट्रपति के संबोधन से पहले वित्त मंत्रालय ने 63 पृष्ठों का लघु आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और आज माननीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पर भाषण दिया। इस प्रकार, वही आंकड़े तीन दिनों में तीन बार सामने आए हैं। प्रत्येक आंकड़े को अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की। 'पीएलएफएस' (जुलाई 2022-जून 2023) और 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, 2023' के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत (ग्रामीण 8.3, शहरी 13.8) है। 25 वर्ष से कम आयु के स्नातकों में बेरोजगारी दर 42.3 प्रतिशत है। यहां तक कि जब स्नातक युवा 30-34 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तब भी बेरोजगारी दर 9.8 प्रतिशत होती है।चिदंबरम ने दावा किया कि वित्त मंत्री ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की बात को स्वीकार नहीं किया और इस पर एक शब्द भी नहीं कहा कि सरकार इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में जानबूझकर उपेक्षा करके सरकार ने जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी कहानी को खत्म कर दिया है और लाखों युवाओं और उनके परिवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, अस्थायी पुरुष कर्मी महिला श्रमिकों की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक कमाते हैं और नियमित पुरुष कर्मचारी महिलाओं की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक कमाते हैं। शहरी महिलाओं के लिए श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 21.9 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के लिए 69.4 प्रतिशत है। शहरी महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर 24.0 प्रतिशत है। चिदंबरम ने कहा, वित्त मंत्री ने किसानों के बारे में बात की। उन्होंने कृषि श्रमिकों सहित किसानों की आत्महत्या की संख्या का खुलासा नहीं किया। 2020, 2021 और 2022 में क्रमश: 10,600, 10,881 और 11,290 किसानों ने खुदकुशी की। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 10 साल के शासन में 'खुशहाल किसान' की बात विरोधाभासी है। चिदंरबम के अनुसार, वित्त मंत्री ने जीडीपी के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में नहीं बात की। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात की, लेकिन उन्होंने वैश्विक भूख सूचकांक में भारत के रैंक या बच्चों में बड़े पैमाने पर कुपोषण के कारण विकास में बाधा और कमज़ोरी के उच्च अनुपात के बारे में बात नहीं की।

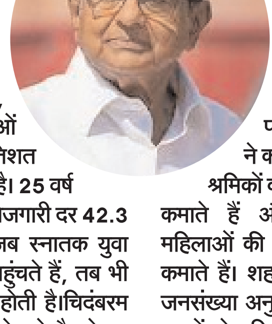

तृणमूल कांग्रेस ने बजट को 'चुनावी शिगूफा' करार दिया

कोलकाता/भाषा। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अंतरिम बजट को लोकसभा चुनाव से पहले ''चुनावी शिगूफा'' करार दिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ''राजनीतिक नौटंकी बंद करने तथा मानव कल्याण को प्राथमिकता देने'' का आग्रह किया। टीएमसी की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की निंदा की।

भट्टाचार्य ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रतिदिन औसतन 30 किसान आत्महत्या करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट में अन्नदाता के कल्याण के लिए आपका दावा पिछले पांच वर्षों में 53,478 किसानों की आत्महत्या का मजाक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिखावा बंद करें और राजनीति के बजाय जीवन को प्राथमिकता दें।

WFS
A Member of the SATS Group
E-AUCTION OF
UNCLAIMED / UNCLEARED CARGO
To be conducted by MSTC LTD
Auction on 8th February 2024
between 10:30 to 16:30 hrs
ITEMS will be displayed at:
WFS (Bengaluru) Pvt. Ltd.
Plot No. C2, Cargo Avenue,
Kempegowda International
Airport, Devanahalli,
Bengaluru-560300
on 05th Feb & 06th Feb 2024
between 10:30 to 16:30 hrs
ITEMS: Pharmacy, Computer
Peripherals, Laptops,
Chargers, Electronic,
Networking components,
Cosmetic, Journals, Machine
Spares and Garments Etc.
For Further Details,
Terms & Conditions
Visit www.mstcecommerce.com

Printed & Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com